राष्ट्रीय छात्रशक्ति

वर्ष-48 ■ अंक-03 ■ अगस्त 2026 ■ ₹10 ■ पृष्ठ-36

भारत भक्ति प्रेरणा का गान

वन्दे मातरम्

रांची: परीक्षा अनियमितता के विरुद्ध अभाविप का प्रदर्शन







राष्ट्रीय छात्रशक्ति

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका

वर्ष-48, अंक-03
अगस्त 2026

संपादक
आशुतोष भटनागर
संपादक मण्डल
संजीव कुमार सिन्हा
अवनीश सिंह
अभिषेक रंजन
अजीत कुमार सिंह

संपादकीय पत्राचार
राष्ट्रीय छात्रशक्ति
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली - 110002.
फोन : 011-23216298
www.chhatrashakti.in
rashtriyachhatrashakti@gmail.com
www.facebook.com/Rchhatrashakti
www.twitter.com/Rchhatrashakti
www.instagram.com/ Rchhatrashakti

स्वामी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक **राजकुमार शर्मा** द्वारा 26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, आई.टी.ओ. के निकट, नई दिल्ली - 110002 से प्रकाशित एवं ओशियन ट्रेडिंग कं., 132 एफ. आई. ई., पटपड़गंज इण्डस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110092 से मुद्रित। **संपादक** *पीआरबी अधिनियम के तहत समाचारों के चयन के लिए जिम्मेवार।

05 राष्ट्रचेतना का अमर निनाद

कुछ गीत ऐसे होते हैं जो समय की सीमाओं से परे जाकर किसी राष्ट्र की सामूहिक चेतना का स्वर बन जाते हैं। वे केवल संगीत...



संपादकीय	04
राजनीति से ऊपर राष्ट्रभाव	08
अभाविप चलाएगी 'कैंपस टू कैंपस वंदे मातरम्' अभियान	11
शाखा : व्यक्ति निर्माण की अभिनव कार्य पद्धति	13
विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं की भूमिका	15
Youth Innovation Holds the Key to India's Agricultural Future	17
Model COP 31 Concludes at IIT Roorkee with Call for Greater Indian Leadership on Climate Action	19
वंदे मातरम के अपमान पर सजा का प्रावधान	18
आपदा में सेवा का संकल्प असम में बाढ़ पीड़ितों के साथ अभाविप	21
नेपथ्य में रहकर राष्ट्र पुनर्निर्माण के साधक थे मदनदास जी	22
विभिन्न मांगों को लेकर अभाविप का प्रदर्शन	22
झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं का संकट युवाओं के भरोसे की परीक्षा	24
परमाणु क्षेत्र में बढ़ता स्वदेशीकरण	24
जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षा अनियमितताओं के विरुद्ध अभाविप का हल्ला बोल, मुख्यमंत्री आवास से विधानसभा तक प्रदर्शन	27
Karnataka State Auctioning the Throne of Education The Curse of Bribery on the Sacred Field of Education!	29
ABVP Protests in Bengaluru, Demands CBI Probe into Alleged KPSC Recruitment Scam	31
पेपर लीक पर कड़ी कार्रवाई करने से क्यों डर रही पंजाब सरकार : अभाविप	33

वैधानिक सूचना : राष्ट्रीय छात्रशक्ति में प्रकाशित लेख एवं विचार तथा रचनाओं में व्यक्त दृष्टिकोण संबंधित लेखकों के हैं। संपादक, प्रकाशक एवं मुद्रक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा।

संपादकीय

शिक्षा की गुणवत्ता तथा परीक्षा की शुचिता सुनिश्चित किए बिना देश को विकास के पथ पर बनाए रखना असंभव है। शिक्षा के मानकों से समझौता वस्तुतः देश के भविष्य के साथ समझौता है जिसके प्रभाव दीर्घकालिक होते हैं। प्रशासनिक एवं संस्थागत लापरवाही तथा उसमें उत्पन्न दोषों को लेकर होने वाला राजनैतिक विरोध, दोनों ही शैक्षिक विकास में अवरोध उत्पन्न करते हैं।

यह मानने में कोई कठिनाई नहीं कि भारत में शिक्षा का ताना-बाना जितना विस्तृत है उसमें जरा सी चूक भी बड़ा असर डाल सकती है। भारत में विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या भी किसी मझोले देश की कुल जनसंख्या से अधिक है। इसमें यदि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की संख्या जोड़ दें तो यह और अधिक हो जाती है। ऐसे में केन्द्रीय परीक्षाओं का आयोजन टेढ़ी खीर है।

इन परीक्षाओं की उपादेयता पर अलग से बहस हो सकती है किन्तु जब तक परीक्षाओं का आयोजन हो रहा है, उनकी शुचिता बनी रहे, यह प्रत्येक संबंधित पक्ष की जिम्मेदारी है। मंहगी शिक्षा का विषय अलग से एक सरोकार बना हुआ है। ऐसे में वर्ष भर तक तैयारी करने के बाद किसी विद्यार्थी का कीमती वर्ष किसी व्यवस्थागत खामी के कारण नष्ट हो जाय तो यह न केवल छात्र के साथ वंचना है अपितु उसके अभिभावक की जेब को भी यह भारी पड़ता है। मानवीय त्रुटियों से इतर भ्रष्टाचार के कारण होने वाली पेपर लीक जैसी घटनाएं न केवल समूची शिक्षा व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह लगाती हैं अपितु समाज की नैतिक दुरावस्था की ओर भी इंगित करती हैं।

शिक्षा और परीक्षा में दृढ़ता से मानकों का पालन करना आवश्यक है। इसलिए नहीं कि छात्र आंदोलित हो सकते हैं, बल्कि इसलिए कि यह देश की छवि ही नहीं बल्कि देश के भविष्य का सवाल है।

पिछले कुछ समय में नीट, एनटीए तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाओं की मानो बाढ़ ही आई हुई है। इससे छात्रों और युवाओं में आक्रोश उत्पन्न होना भी स्वाभाविक ही है। स्वतः स्फूर्त युवा आंदोलन भी इसकी स्वाभाविक परिणति है। इस स्थिति का राजनैतिक लाभ उठाने की प्रवृत्ति भी अस्वाभाविक नहीं कही जा सकती। किन्तु दलगत राजनैतिक स्वार्थ के चलते आंदोलन को हिंसक मोड़ देने की चेष्टा निंदनीय है।

हमारे सामने एक ओर दिल्ली में जंतर-मंतर पर होने वाले आंदोलन का उदाहरण है जहां एकत्र आंदोलनकारी छात्रों की आवाज एजेण्डा आधारित राजनैतिक-सामाजिक दलों के प्रतिनिधियों, एनजीओ वालों तथा धुर वामपंथी संगठनों की ढ़पलियों के शोर के बीच दब गयी। वहीं दूसरी ओर झारखण्ड का छात्र आन्दोलन है जिसने अत्यंत संयम का परिचय दिया और राजनैतिक दलों का मोहरा बनने से बच गए। जंतर-मंतर के एक्टिविस्ट अपनी अल खिचड़ी पकाने रांची भी गए किन्तु वहां उनकी दाल न गल सकी।

शिक्षा और परीक्षा में दृढ़ता से मानकों का पालन करना आवश्यक है। इसलिए नहीं कि छात्र आंदोलित हो सकते हैं, बल्कि इसलिए कि यह देश की छवि ही नहीं बल्कि देश के भविष्य का सवाल है। इसके लिए व्यवस्था और प्रशासन को संवेदनशील बनाये जाने की जरूरत है, जवाबदेही निश्चित किए जाने की आवश्यकता है।

यह संभव है कि राजनैतिक उद्देश्यों के लिए इन सकारात्मक प्रयासों का विरोध किया जाय, लेकिन इस दवाब के बावजूद भी आगे बढ़ना ही होगा। यदि देश में राष्ट्रगीत गाने का राजनैतिक विरोध खड़ा किया जा सकता है तो कुछ भी संभव है। लेकिन इस सब बाधाओं को पार करते हुए यदि विकसित भारत का स्वप्न पूरा करना है तो शिक्षा और परीक्षा की शुचिता और गुणवत्ता को सुनिश्चित करना ही होगा।

विविध समाचारों तथा नियमित स्तंभों के साथ यह अंक आपके समक्ष प्रस्तुत है।

स्वातंत्र्य पर्व की शुभकामना सहित,

आपका

संपादक



वन्दे मातरम् ।
सुजलाम् सुफलाम् मलयजशीतलाम्
शस्य श्यामलाम् मातरम् ।
शुभ्रज्योत्स्नापुलकितयामिनीम्
फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीम्
सुहासिनीम् सुमधुरभाषिणीम्
सुखदाम् वरदाम् मातरम् ।
कोटिकोटिकंठकलकलनिनादकराले
कोटिकोटिभुजैर्धृतखरकरवाले
अबला केनो मां एतो बले
बहुबलधारिणीम् नमामि तारिणीम्
रिपुदलवारिणीम् मातरम् ।
तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदि तुमि मर्म
त्वं हि प्राणाः शरीरे
बाहु ते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति
तोमरई प्रतिमा गड़ि मंदिरे, मंदिरे, मातरम् ।
त्वं हि दुर्गा दशप्रहरणधारिणी
कमला कमलदलविहारिणी
वाणी विद्यादायिणीम्
नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलाम्
सुजलाम् सुफलाम् मातरम् ।
श्यामलाम् सरलाम् सुस्मिताम् भूषिताम्
धरणीम् भरणीम् मातरम्
वन्दे मातरम् ।
।। भारत माता की जय ।।

राष्ट्रचेतना का अमर निनाद

■ अजीत कुमार सिंह

कुछ गीत ऐसे होते हैं जो समय की सीमाओं से परे जाकर किसी राष्ट्र की सामूहिक चेतना का स्वर बन जाते हैं। वे केवल संगीत और शब्दों की रचना नहीं रहते, बल्कि इतिहास के निर्णायक क्षणों में समाज की आकांक्षाओं, संघर्षों और संकल्पों को अभिव्यक्ति देते हैं। 'वन्देमातरम्' ऐसा ही एक अमर राष्ट्रगीत है, जिसने भारत के स्वाधीनता संग्राम को स्वर दिया, राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया और मातृभूमि के प्रति श्रद्धा एवं समर्पण की भावना को जन-जन तक पहुंचाया। 'वन्देमातरम्' के 150 वर्ष पूर्ण होना केवल एक ऐतिहासिक रचना की वर्षगांठ नहीं है। यह उस पुनीत यात्रा को स्मरण करने का अवसर है, जिसमें भारतीय समाज ने पराधीनता के बीच अपने सांस्कृतिक स्वत्व को पहचाना, अपनी मातृभूमि के प्रति आत्मीयता को स्वर दिया और अंततः स्वतंत्रता के संकल्प को जनांदोलन में परिवर्तित किया।

उन्नीसवीं शताब्दी का उत्तरार्ध भारतीय इतिहास का संक्रमणकाल था। अंग्रेजी शासन राजनीतिक नियंत्रण के साथ-साथ भारतीय समाज के आत्मविश्वास को भी प्रभावित कर रहा था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद औपनिवेशिक शासन और अधिक कठोर हुआ। ऐसे समय में भारतीय साहित्य-संस्कृति ने राष्ट्र चेतना को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय ने 'वन्देमातरम्' की रचना की। बाद में इसे उनके प्रसिद्ध उपन्यास 'आनंदमठ' (1882) में स्थान मिला। यह रचना उस भारतीय दृष्टि की अभिव्यक्ति थी, जिसमें मातृभूमि केवल भौगोलिक भूखंड नहीं, बल्कि जीवनदायिनी 'मां' के रूप में प्रतिष्ठित होती है।

'सुजलाम्, सुफलाम्, मलयज-शीतलाम्' जैसे

शब्द भारत की प्रकृति, कृषि-संपन्नता, जल, वायु और जीवनदायिनी शक्ति का चित्र उपस्थित करते हैं। इस प्रकार गीत में राष्ट्रप्रेम किसी विचार के रूप में नहीं, बल्कि उस भूमि के प्रति आत्मीयता और कृतज्ञता के रूप में सामने आता है, जिसने पीढ़ियों को जीवन दिया है। यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी-इसने राष्ट्र को केवल राजनीतिक इकाई के रूप में नहीं, बल्कि सांस्कृतिक एकात्मता के रूप में देखने की दृष्टि प्रदान की।

जनांदोलन में महत्ती भूमिका निर्वहन

'वन्देमातरम्' का प्रभाव साहित्यिक संसार तक सीमित नहीं रहा। 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा इसके गायन ने इसे व्यापक राष्ट्रीय मंच प्रदान किया। इसके बाद यह गीत सार्वजनिक सभाओं, राष्ट्रीय आंदोलनों और स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत क्रांतिकारियों के बीच नियमित रूप से गाया जाने लगा।

बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में जब बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन उभरा, तब 'वन्देमातरम्' उसकी चेतना का प्रमुख स्वर बन गया। विद्यालयों, सार्वजनिक सभाओं और संगोष्ठियों में इसका सामूहिक गायन होने लगा। ब्रिटिश शासन ने इसकी जन-एकजुट करने वाली क्षमता को महसूस किया और विभिन्न स्थानों पर इसके सार्वजनिक गायन पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए। किन्तु किसी गीत की शक्ति केवल उसके शब्दों में नहीं होती; उसकी वास्तविक शक्ति उस सामूहिक भावना में होती है, जिसे वह जागृत करता है। 'वन्देमातरम्' जन-समान्य को जागृत करने में सफल हुआ।

वन्दे मातरम् का उद्घोष स्वदेशी, स्वावलंबन और औपनिवेशिक शासन के विरोध से जुड़ता चला गया। अरविंद घोष जैसे राष्ट्रवादी चिंतकों ने इसमें भारतीय राष्ट्रचेतना की आध्यात्मिक अभिव्यक्ति देखी। देश के विभिन्न क्षेत्रों और भाषाओं में इसके प्रसार ने इसे एक व्यापक राष्ट्रीय प्रतीक का स्वरूप दिया।

आत्मविश्वास का प्रतीक वंदेमातरम्

स्वाधीनता आंदोलन के अनेक चरणों में 'वन्देमातरम्' प्रतिरोध और आत्मविश्वास का प्रतीक बनकर सामने आया। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष करने वाले के लिए यह मातृभूमि के प्रति निष्ठा और बलिदान की भावना का उद्घोष था।

'वन्देमातरम्' की कहानी किसी एक गीत की कहानी नहीं है। यह भारतीय राष्ट्रचेतना के जागरण की कहानी है। यह उस यात्रा की कहानी है, जिसमें साहित्य ने चेतना को स्वर दिया, चेतना ने आंदोलन को जन्म दिया और आंदोलन ने स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। डेढ़ शताब्दी पहले इस गीत ने पराधीन भारत को अपने स्वत्व का बोध कराया था।

1905 का बंग-भंग आंदोलन इस दृष्टि से विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। 'वन्देमातरम्' स्वदेशी आंदोलन की सभाओं और संगोष्ठियों में गूंजता रहा। इसके बाद यह भारत से बाहर सक्रिय राष्ट्रवादी समूहों तक भी पहुंचा। मैडम भीकाजी कामा द्वारा 1907 में विदेश की धरती पर फहराए गए भारतीय ध्वज से लेकर भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों और राष्ट्रवादी प्रकाशनों तक इसकी उपस्थिति दिखाई देती है।

इस प्रकार 'वन्देमातरम्' केवल भारत के भीतर राजनीतिक प्रतिरोध का स्वर नहीं रहा; वह विदेशों में बसे भारतीयों के लिए भी मातृभूमि से जुड़ाव और स्वतंत्रता की आकांक्षा का प्रतीक बन गया।

सांस्कृतिक चेतना

'वन्देमातरम्' को समझने के लिए भारतीय राष्ट्रबोध की प्रकृति को समझना आवश्यक है। भारतीय परंपरा में भूमि के साथ संबंध केवल अधिकार का नहीं, बल्कि मातृत्व और कर्तव्य का है। अथर्ववेद का उद्घोष-'माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः'-पृथ्वी को माता और मनुष्य को उसका पुत्र मानता है। इसी सांस्कृतिक चेतना में 'वन्देमातरम्' का भाव सहज रूप से प्रतिष्ठित होता है।

गीत में मां के रूप में दिखाई देने वाली मातृभूमि केवल मिट्टी नहीं है। वह नदियों की धारा है, खेतों की हरियाली है, पर्वतों की स्थिरता है, वायु की शीतलता है

और करोड़ों भारतीयों के सामूहिक जीवन का आधार है। इसलिए 'वन्देमातरम्' का राष्ट्रप्रेम केवल राष्ट्रवाद तक सीमित नहीं है। उसमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और राष्ट्र के प्रति उत्तरदायित्व का भाव एक साथ उपस्थित है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों को लेकर संविधान सभा में विचार हुआ। 'जन गण मन' और 'वन्देमातरम्' दोनों के ऐतिहासिक महत्व को स्वीकार किया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा में डा. राजेंद्र प्रसाद ने घोषणा की कि 'जन गण मन' भारत का राष्ट्रगान होगा और 'वन्देमातरम्', जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, को समान रूप से सम्मान दिया जाएगा। इस निर्णय ने स्वतंत्रता आंदोलन की स्मृति और राष्ट्रीय जीवन में 'वन्देमातरम्' की विशिष्ट भूमिका को औपचारिक सम्मान प्रदान किया। एक राष्ट्रगान के रूप में 'जन गण मन' और राष्ट्रगीत के रूप में 'वन्देमातरम्'-दोनों भारतीय राष्ट्रीय जीवन में अपनी-अपनी विशिष्ट ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक भूमिका के साथ प्रतिष्ठित हुए।

'वन्देमातरम्' की डेढ़ सौ वर्ष की यात्रा हमें अतीत का स्मरण कराने के साथ वर्तमान का प्रश्न भी देती है। जिस समय यह गीत रचा गया था, भारत पराधीन था। तब स्वतंत्रता सबसे बड़ा राष्ट्रीय लक्ष्य था। आज भारत स्वतंत्र है। इसलिए 'वन्देमातरम्' का अर्थ भी हमारे लिए एक नए संदर्भ में सामने आता है।

आज राष्ट्रभक्ति का अर्थ केवल विदेशी सत्ता के विरुद्ध संघर्ष नहीं, बल्कि स्वतंत्र भारत को अधिक सक्षम, समृद्ध, न्यायपूर्ण और आत्मविश्वासी बनाने के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण केवल शासन या संस्थाओं का कार्य नहीं है। यह प्रत्येक नागरिक के छोटे-बड़े कार्यो से निर्मित होता है।

किसान जब अपनी भूमि को समृद्ध करता है, सैनिक जब सीमा की रक्षा करता है, शिक्षक जब नई पीढ़ी में ज्ञान और संस्कार का संचार करता है, वैज्ञानिक जब देश की क्षमताओं को बढ़ाता है, उद्यमी जब रोजगार और नवाचार के अवसर पैदा करता है और युवा जब अपनी प्रतिभा को राष्ट्रहित से जोड़ता है-तब 'वन्देमातरम्' अपने वास्तविक अर्थ में जीवन्त होता है।

नई पीढ़ी के लिए राष्ट्रबोध

आज का युवा एक ऐसे समय में जी रहा है, जब तकनीक ने दुनिया को अभूतपूर्व रूप से निकट ला दिया है। वैश्विक अवसरों के बीच अपनी सांस्कृतिक जड़ों और राष्ट्रीय पहचान के प्रति सजग रहना पहले से अधिक आवश्यक हो गया है। 'वन्देमातरम्' नई पीढ़ी को अतीत में लौटने का आह्वान नहीं करता; वह अपनी जड़ों से जुड़कर भविष्य के निर्माण करने की प्रेरणा देता है। इस गीत का मूल संदेश है-जिस मातृभूमि ने हमें जन्म दिया, उसके प्रति केवल अधिकार नहीं, दायित्व भी है; केवल गौरव नहीं, योगदान भी है; केवल स्मरण नहीं, कर्म भी है। यही कारण है कि डेढ़ सौ वर्ष बाद भी 'वन्देमातरम्' का महत्व समाप्त नहीं हुआ है। परिस्थितियां बदली हैं, चुनौतियां बदली हैं, लेकिन मातृभूमि के प्रति श्रद्धा और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का भाव आज भी उतना ही प्रासंगिक है।

अमर पुकार

'वन्देमातरम्' की कहानी किसी एक गीत की कहानी नहीं है। यह भारतीय राष्ट्रचेतना के जागरण की कहानी है। यह उस यात्रा की कहानी है, जिसमें साहित्य ने चेतना को स्वर दिया, चेतना ने आंदोलन को जन्म दिया और आंदोलन ने स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। डेढ़ शताब्दी पहले इस गीत ने पराधीन भारत को अपने स्वत्व का बोध कराया था। आज वही गीत स्वतंत्र भारत को यह स्मरण करा सकता है कि स्वतंत्रता केवल प्राप्त करने की वस्तु नहीं, बल्कि निरंतर सार्थक करने का दायित्व है।

इसलिए 'वन्देमातरम्' का उच्चारण केवल अतीत की स्मृति नहीं है। यह वर्तमान का संकल्प और भविष्य की जिम्मेदारी भी है। मातृभूमि के प्रति श्रद्धा, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य और समाज के प्रति उत्तरदायित्व-इन तीनों भावों का समन्वित स्वर ही 'वन्देमातरम्' है।

डेढ़ सौ वर्षों की इस यात्रा के बाद भी वह स्वर उतना ही जीवंत है- वन्देमातरम्। ■



राजनीति से ऊपर राष्ट्रभाव

■ अवनीश कुमार सिंह

भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में कुछ शब्द केवल शब्द नहीं रहे। वे संघर्ष की आवाज बन गए। उनमें 'वंदे मातरम्' सबसे प्रमुख है। यह गीत भारत की धरती को मां के रूप में देखने वाली उस भावना का प्रतीक बना, जिसने गुलामी के दौर में लाखों भारतीयों के भीतर स्वाधीनता की चेतना जगाई।

7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जिन शब्दों को कविता का रूप दिया, वे आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन का उद्घोष बन गए। 1882 में उनके उपन्यास आनंदमठ में यह गीत प्रकाशित हुआ। 1896 में रवींद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस के अधिवेशन में इसका गायन किया। इसके बाद 'वंदे मातरम्' धीरे-धीरे बंगाल की सीमाओं से निकलकर पूरे देश की राष्ट्रीय चेतना का हिस्सा बन गया।

अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष कर रहे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए यह केवल गीत नहीं था। यह मातृभूमि के प्रति समर्पण का भाव था। यही कारण है कि 'वंदे मातरम्' सुनते ही उस दौर के संघर्ष, बलिदान और स्वाधीनता की आकांक्षा की स्मृति सामने आती है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि आज यही राष्ट्रगीत राजनीतिक विवाद का विषय बना हुआ है।

गीत से ज्यादा राजनीति महत्वपूर्ण क्यों?

विवाद का मूल 1937 के उस निर्णय से जुड़ा है,

जब कांग्रेस ने राष्ट्रीय कार्यक्रमों में 'वंदे मातरम्' के शुरुआती दो पदों के प्रयोग का निर्णय लिया। इसके पीछे तर्क दिया गया कि गीत के आगे के पदों में दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती जैसे हिंदू देवी-स्वरूपों का उल्लेख कुछ मुस्लिम नेताओं को आपत्तिजनक लगता है।

यहां से एक बड़ा सवाल पैदा होता है। क्या किसी रचना के कुछ अंशों को इसलिए अलग कर देना उचित है क्योंकि उनमें भारतीय संस्कृति और उसकी धार्मिक प्रतीक-परंपरा का उल्लेख है? उस समय कांग्रेस ने सांप्रदायिक तनाव की आशंका को देखते हुए रास्ता निकाला। समिति में रवींद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद और जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रमुख लोग शामिल थे। अंततः राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए शुरुआती दो पदों के प्रयोग की व्यवस्था बनी। यह उस समय की राजनीतिक परिस्थिति का निर्णय था। लेकिन आज, लगभग नौ दशक बाद, वही फैसला नए राजनीतिक संघर्ष का आधार बन गया है।

राष्ट्रभाव को टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता

'वंदे मातरम्' की मूल भावना मातृभूमि की वंदना है। भारत को मां मानने की कल्पना भारतीय सभ्यता में नई नहीं है। यहां धरती को मां कहा गया। नदियों को मां का सम्मान मिला। प्रकृति को पूजनीय माना गया। यही सांस्कृतिक दृष्टि भारत की पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा रही है।

इसलिए प्रश्न केवल इतना नहीं है कि गीत के कितने पद गाए जाएं। प्रश्न यह भी है कि क्या राष्ट्रीय प्रतीकों और राष्ट्रीय भावनाओं को राजनीतिक सुविधा के अनुसार देखा जाना चाहिए? राष्ट्रगीत किसी राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं है। यह किसी सरकार का गीत नहीं है। यह उस भारत की स्मृति है, जिसने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया।

इसलिए 'वंदे मातरम्' पर बहस हो सकती है। ऐतिहासिक परिस्थितियों की चर्चा हो सकती है। लेकिन उसके मूल राष्ट्रभाव को राजनीतिक खांचों में बांटना उचित नहीं होगा।

गीत के रचनाकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय नहीं हैं आज हमारे सामने। स्वतंत्रता सेनानियों की वह पीढ़ी भी नहीं है जिसने इस गीत को अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष का स्वर बनाया। आज हमारे सामने केवल राजनीतिक दल हैं, उनके आरोप हैं और उनके अपने-अपने राजनीतिक नैरेटिव हैं।

1937 को आज की राजनीति से कैसे जोड़ें?

इतिहास को समझना जरूरी है। लेकिन इतिहास का उपयोग वर्तमान की राजनीति के लिए किस सीमा तक किया जाए, यह भी विचार का विषय है। 1937 का

वंदे मातरम् का पूर्ण गायन राष्ट्रीय चेतना के पुनर्जागरण का अवसर : अभाविप

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से इसके पूर्ण गायन को राष्ट्रीय चेतना और गौरव का ऐतिहासिक अवसर बताया। अभाविप ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस केवल उत्सव का दिन नहीं, बल्कि राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले ज्ञात-अज्ञात बलिदानियों के त्याग और संकल्प को स्मरण करने का अवसर है।

अभाविप ने कहा कि वंदे मातरम् भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रीय चेतना, स्वाभिमान और राष्ट्रभाव का अमर उद्घोष रहा है। रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसके गायन से लेकर 1905 के बनारस अधिवेशन में सरला देवी चौधरानी द्वारा इसके गायन और स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न चरणों में क्रांतिकारियों एवं स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा इसके उद्घोष तक, वंदे मातरम् ने देशवासियों में स्वाधीनता और मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना को प्रबल किया।

अभाविप ने भगत सिंह, रानी गाइडिन्ल्यू, कनकलता बरुआ सहित असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों और जनजातीय वीर-वीरांगनाओं के संघर्ष का उल्लेख करते हुए कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन की राष्ट्रभाव से ओतप्रोत विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाना आज की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। परिषद ने युवाओं से आह्वान किया कि वे स्वतंत्रता सेनानियों के संकल्प को आत्मसात करते हुए 2047 तक विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

भारत आज के भारत से बिल्कुल अलग था। अंग्रेजी शासन था। स्वतंत्रता का संघर्ष चल रहा था। हिंदू-मुस्लिम संबंधों में तनाव बढ़ रहा था। मुस्लिम लीग अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर रही थी। कांग्रेस भी व्यापक राष्ट्रीय समर्थन बनाए रखने की चुनौती से गुजर रही थी। ऐसे वातावरण में लिया गया निर्णय आज के लोकतांत्रिक भारत में उसी रूप में लागू हो, यह जरूरी नहीं।

वंदे मातरम् के पूर्ण गायन को रोकने के प्रयास की निंदा

कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम् के पूर्ण गायन को कथित रूप से रोकने के प्रयास पर अभाविप ने कड़ी आपत्ति जताई। परिषद ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिस वंदे मातरम् ने देशवासियों में स्वाधीनता की चेतना और राष्ट्रभाव को जागृत किया, उसके प्रति असम्मान उन अमर बलिदानियों की स्मृति के प्रति भी असंवेदनशीलता है, जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर किया।

अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री डा. वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूर्ण होने पर लाल किले की प्राचीर से पूर्ण वंदे मातरम् का गायन अमर बलिदानियों के प्रति सच्चा सम्मान है। उन्होंने कहा कि संसद द्वारा वंदे मातरम् के सम्मान एवं गायन को वैधानिक संरक्षण दिया जाना अभिनंदनीय है।

उन्होंने कहा कि सरकार की युवा-केंद्रित पहलें युवाओं की प्रतिभा और क्षमता को अवसरों से जोड़कर विकसित भारत की नींव मजबूत करेंगी। वहीं, कांग्रेस मुख्यालय की घटना पर उन्होंने कहा कि यह केवल एक गीत का विषय नहीं, बल्कि उन बलिदानियों की गौरवशाली विरासत का प्रश्न है, जिन्होंने वंदे मातरम् के उद्घोष के साथ मातृभूमि के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति सम्मान जरूरी

आज सबसे बड़ा प्रश्न राजनीतिक दलों से ज्यादा समाज के सामने है। क्या हम राष्ट्रीय प्रतीकों को दलगत राजनीति से ऊपर रख सकते हैं? राष्ट्रगान हो या राष्ट्रगीत। तिरंगा हो या संविधान। इनका सम्मान केवल कानून के डर से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चेतना से होना चाहिए। 'वंदे मातरम्' को लेकर यदि किसी नागरिक के मन में ऐतिहासिक या सांस्कृतिक प्रश्न हैं तो उनका उत्तर संवाद से दिया जाना चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय भावनाओं का अपमान किसी भी पक्ष से स्वीकार्य नहीं होना चाहिए।

राष्ट्रभक्ति का अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति हर बात पर एक जैसा विचार रखे। लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक हैं। लेकिन मतभेद और राष्ट्रविरोध एक ही बात नहीं हैं। इसी तरह राष्ट्रप्रेम का अर्थ भी यह नहीं कि इतिहास के हर निर्णय को बिना सवाल स्वीकार कर लिया जाए।

असली लड़ाई राष्ट्रभाव की है

आज 'वंदे मातरम्' का विवाद हमें एक बड़े प्रश्न के सामने खड़ा करता है। क्या भारत की राष्ट्रीय पहचान को राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से परिभाषित किया जाएगा या उसकी हजारों वर्ष पुरानी सांस्कृतिक चेतना के आधार पर?

भारत की शक्ति उसकी विविधता में है। लेकिन विविधता का अर्थ राष्ट्रीय भावनाओं का विखंडन नहीं हो सकता। अलग-अलग भाषाएं, पूजा-पद्धतियां और परंपराएं भारत की पहचान का हिस्सा हैं। इनके बीच एक साझा सूत्र भी है मातृभूमि के प्रति श्रद्धा। 'वंदे मातरम्' इसी साझा भाव का प्रतीक है।

आज जरूरत किसी राजनीतिक दल को विजेता और किसी को पराजित घोषित करने की नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हम उस भावना को समझें जिसने इस गीत को स्वतंत्रता आंदोलन का स्वर बनाया था। क्योंकि अंततः वंदे मातरम् किसी दल का नारा नहीं है। यह उस भारत की वंदना है, जिसके लिए असंख्य लोगों ने अपना वर्तमान कुर्बान कर दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां स्वतंत्र भारत में सांस ले सकें। और शायद यही वह बात है, जिसे आज की राजनीति के शोर में सबसे ज्यादा याद रखने की जरूरत है। ■



अभाविप चलाएगी 'कैंपस टू कैंपस वंदे मातरम्' अभियान

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) की केंद्रीय कार्यसमिति की दो दिवसीय बैठक 1 एवं 2 अगस्त को जगद्गुरु आदि शंकराचार्य की पावन जन्मस्थली एर्नाकुलम, केरलम में संपन्न हुई। बैठक में देश की वर्तमान शैक्षणिक एवं राष्ट्रीय परिस्थितियों, संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा तथा आगामी वर्ष की कार्ययोजना पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया। बैठक में प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता, राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' के सम्मान, युवाओं की सक्रिय भागीदारी तथा संगठन के विस्तार सहित अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिए गए।

बैठक में झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी), बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी), कर्नाटक लोक सेवा आयोग (केपीएससी) तथा पंजाब सहित विभिन्न राज्यों में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक की घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। अभाविप ने विद्यार्थियों की न्यायोचित मांगों और उनके लोकतांत्रिक आंदोलनों को पूर्ण समर्थन देने की घोषणा की। परिषद ने समाज के विभिन्न संगठनों और नागरिकों से भी विद्यार्थियों के इस संघर्ष में सहभागिता का आह्वान किया।

अभाविप का कहना है कि निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी का अधिकार है। झारखंड में प्रश्नपत्र लीक की घटनाओं के सामने आने के बाद परिषद ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के साथ हस्ताक्षर अभियान चलाया तथा सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध-प्रदर्शन किए। परिषद ने कहा कि परीक्षा व्यवस्था को पूर्णतः पारदर्शी एवं त्रुटिरहित बनाने के लिए आवश्यक संस्थागत सुधार किए जाना अभी बाकी हैं। इसी क्रम में

नीट परीक्षा में सामने आई अनियमितताओं के बाद गठित उच्चस्तरीय समिति के समक्ष अभाविप परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए अपने विस्तृत सुझाव एवं अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगी।

बैठक में संसद द्वारा राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किए जाने और राष्ट्रगीत 'वन्दे मातरम्' के सम्मान को विधिक संरक्षण दिए जाने का स्वागत किया गया। अभाविप ने इसे राष्ट्रीय चेतना, स्वतंत्रता संग्राम की विरासत और भारत की सांस्कृतिक अस्मिता के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।



परिषद ने आगामी समय में 'वन्दे मातरम् @150 वर्ष : कैंपस टू कैंपस वन्दे मातरम्' अभियान को देशभर के शैक्षणिक परिसरों तक ले जाने का निर्णय लिया है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर तिरंगा रैली, 'एक गांव-एक तिरंगा' अभियान और सामूहिक वंदे मातरम् गायन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों एवं समाज में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकात्मता की भावना को व्यापक बनाने की योजना है।

बैठक में 'स्क्रीन टाइम टू एक्टिविटी टाइम' अभियान की आगामी गतिविधियों पर भी चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त संत शिरोमणि रविदास जी के 650वें प्राकट्य वर्ष, श्री गुरु तेगबहादुर जी के बलिदान के 350 वर्ष, आपातकाल विरोधी आंदोलन के 50 वर्ष, अखिल भारतीय छात्रावास सर्वेक्षण, 72वें राष्ट्रीय अधिवेशन, SEIL@60, प्रा. यशवंतराव केलकर युवा पुरस्कार, अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी संपर्क, ओवरसीज कार्य, संगठनात्मक विस्तार तथा कार्यशाला संस्कृति जैसे विषयों पर भी कार्ययोजना निर्धारित की गई।

आगामी दिनों में केरलम के शैक्षणिक परिसरों में 'कैंपस टू कैंपस वन्दे मातरम्' और 'स्क्रीन टाइम टू एक्टिविटी टाइम' अभियानों को व्यापक स्तर पर संचालित किया जाएगा। परिषद का उद्देश्य इन अभियानों के माध्यम से विद्यार्थियों में राष्ट्रभक्ति, सकारात्मक परिसर संस्कृति, नेतृत्व क्षमता और सक्रिय जनभागीदारी को बढ़ावा देना है।

अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री डा. वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि एर्नाकुलम में हुई बैठक में शिक्षा, संगठन, समसामयिक राष्ट्रीय विषयों और आगामी वर्ष की कार्ययोजना पर सार्थक मंथन हुआ। उन्होंने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक की घटनाएं देश की परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न खड़े करती हैं और अभाविप विद्यार्थियों की न्यायोचित मांगों के साथ मजबूती से खड़ी है।

उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना आवश्यक है। इसके लिए अभाविप उच्चस्तरीय समिति के समक्ष परीक्षा प्रणाली में आवश्यक संस्थागत सुधारों से संबंधित विस्तृत सुझाव प्रस्तुत करेगी।

डा. सोलंकी ने 'वन्दे मातरम्' को भारत की स्वतंत्रता यात्रा और राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक बताते हुए कहा कि इसके सम्मान को विधिक संरक्षण मिलना ऐतिहासिक निर्णय है। उन्होंने कहा कि अभाविप 'कैंपस टू कैंपस वन्दे मातरम्', 'एक गांव-एक तिरंगा', तिरंगा रैलियों और सामूहिक वन्दे मातरम् गायन के माध्यम से राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकात्मता और संवैधानिक कर्तव्यों के प्रति जनजागरण करेगी।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्रीय कार्यसमिति में तय कार्ययोजना को अभाविप के कार्यकर्ता जनभागीदारी के साथ आगे बढ़ाएंगे और छात्रशक्ति को राष्ट्रशक्ति के रूप में संगठित करने के संकल्प को और सशक्त करेंगे। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)



शाखा : व्यक्ति निर्माण की अभिनव कार्य पद्धति

■ डा. रजत शर्मा

दैनिक मिलन की अभिनव कार्य पद्धति 'शाखा' का विकास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विशेषता रही है। विखंडित हिंदू समाज की स्थिति को देखकर डा. केशव बलिराम हेडगेवार ने हिंदू समाज को संगठित करने के उद्देश्य से इस कार्य पद्धति का चयन किया। हिंदू समाज आरंभ से ही उत्सवों, मंदिरों, मेलों, तीर्थों आदि स्थानों पर आपस में मिलता-जुलता आया है। यह आपसी संपर्क ही विविधता में एकता के नैसर्गिक गुण के रूप में भारत की विशिष्ट पहचान बनाता रहा है। इसी प्रयोगसिद्ध पद्धति का विकास आगे चलकर 'शाखा' के रूप में हुआ।

कहा जाए तो 'शाखा' हिंदू समाज के जुड़कर रहने का विश्वास है, हिंदू समाज के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करने की प्रेरणा है तथा समाज एवं राष्ट्र के उत्थान के लिए एकजुट हुए सदस्यों के संस्कार का माध्यम है। शाखा में कोई निश्चित सदस्यता नहीं होती, बल्कि शाखा सभी के लिए है। कोई भी व्यक्ति इसमें सम्मिलित हो सकता है। जाति, धर्म, वर्ण, व्यवसाय आदि का भेद शाखा में स्वीकार्य नहीं है।

'शाखा' सभी कार्यों का अधिष्ठान है, क्योंकि प्रत्येक कार्य के लिए आवश्यक योग्य, समर्पित एवं ध्येयनिष्ठ स्वयंसेवकों का निर्माण इसी पद्धति से संभव है। विगत सौ वर्षों के संघ कार्य ने इसे सिद्ध किया है। संघ की दैनिक शाखा व्यक्ति निर्माण की एक प्रभावी पद्धति है। हालांकि, यह कहना उचित नहीं होगा कि शाखा का स्वरूप स्थायी और अपरिवर्तनीय है। स्थान, काल और परिस्थिति के अनुरूप एक घंटे की शाखा में कार्यक्रमों में परिवर्तन हो सकता है। यदि कुछ अपरिवर्तनशील है तो वह है ध्वज और प्रार्थना।

शाखा के दैनिक कार्यक्रमों के माध्यम से उत्साह, पराक्रम, निर्भरता, अनुशासन, विजय-वृत्ति, अखंड रूप से कार्य करने का अभ्यास, नियमितता, परस्पर सहयोग, आत्मविश्वास, सामाजिकता और राष्ट्रीय भाव जैसे गुणों का

निरंतर विकास होता रहता है। शाखा में आने से स्वयंसेवकों के मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार मूर्तिकार हथौड़े और छैनी से पत्थर को तराशकर एक सुंदर मूर्ति का निर्माण करता है, उसी प्रकार 'शाखा' समाज में व्यक्ति को संस्कारित और तराशकर स्वयंसेवक के रूप में तैयार करती है। यही लक्ष्य शाखा के मूल में निरंतर गतिमान रहता है।

'शाखा' का स्वरूप डॉ. हेडगेवार की अनुभव-दृष्टि से प्रेरित होकर बैठकों में धीरे-धीरे विकसित हुआ। डॉ. हेडगेवार ने 27 सितंबर, रविवार को विजयादशमी के दिन अपने घर में घोषणा की कि, *'हम आज संघ का प्रारंभ कर रहे हैं, जिसका लक्ष्य भारत की पूर्ण स्वतंत्रता और भारत का परम वैभव है।'* आरंभ में रविवार को ड्रिल, मार्च आदि का प्रशिक्षण दिया जाता था। गुरुवार और रविवार को राष्ट्रीय विषयों पर चर्चा होती थी तथा अन्य दिनों में अलग-अलग अखाड़ों में जाने का क्रम रहता था। शारीरिक, सैनिक और राजकीय वर्ग भी प्रारंभ हुए। स्वयंसेवक के शारीरिक एवं बौद्धिक विकास को ध्यान में रखते हुए शाखा में विभिन्न कार्यक्रम निर्धारित किए गए।

'शाखा' सभी कार्यों का अधिष्ठान है, क्योंकि प्रत्येक कार्य के लिए आवश्यक योग्य, समर्पित एवं ध्येयनिष्ठ स्वयंसेवकों का निर्माण इसी पद्धति से संभव है। विगत सौ वर्षों के संघ कार्य ने इसे सिद्ध किया है। संघ की दैनिक शाखा व्यक्ति निर्माण की एक प्रभावी पद्धति है। जिस प्रकार मूर्तिकार हथौड़े और छैनी से पत्थर को तराशकर एक सुंदर मूर्ति का निर्माण करता है, उसी प्रकार 'शाखा' समाज में व्यक्ति को संस्कारित और तराशकर स्वयंसेवक के रूप में तैयार करती है।

हालांकि, ये कार्यक्रम केवल शारीरिक और बौद्धिक गतिविधियों तक सीमित नहीं थे। इनके मूल में स्वयंसेवकों में चारित्रिक, वैचारिक, सांस्कृतिक, नैतिक एवं राष्ट्र-केंद्रित दृष्टि का विकास करना रहा है। उदाहरण के लिए, कबड्डी का खेल स्वयंसेवक में साहस, संघर्ष, चुनौतियों से टकराने, सामूहिक रूप से कार्य करने और सेवाभाव जैसे गुणों का विकास करता है। इसी प्रकार खेल के माध्यम से जीवन के संघर्षों का सामना करने और सामूहिकता के भाव को आत्मसात करने की प्रेरणा मिलती है।

श्री माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर 'गुरुजी' का विचार था कि *'संस्कारों के लिए योग्य वातावरण की आवश्यकता होती है। बाहर तथा अंदर के वातावरण के प्रभाव के कारण जलती अंगीठी में ठंडा कोयला दहकने लगता है, बाहर निकालने पर बुझ जाता है। संघ स्थान का तेजस्वी वातावरण योग्य संस्कार देने में सक्षम है।'*

प्रत्येक स्वयंसेवक साथ-साथ चलने, बोलने और समान बोध के साथ पूर्ण समरसता के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से संगठन मंत्र का उच्चारण करता है। व्यक्ति से समूह, समूह से समाज और समाज से राष्ट्र, उसी परम वैभव के लक्ष्य की ओर बढ़े-शाखा में स्वयंसेवक इसी दृष्टि को आत्मसात करता है।

यदि शाखा में होने वाले शारीरिक एवं बौद्धिक कार्यक्रमों से इतर भी विचार करें तो संघस्थान पर होने वाले कार्यक्रमों की एक विशेषता 'समता' भी है। शाखाओं में की जाने वाली समता में दक्ष, आरम, दक्षिण वृत्त, वाम वृत्त, प्रचल, स्तभ, उपविश, उत्तिष्ठ आदि आज्ञाओं का भी उद्देश्य है। इन आज्ञाओं के माध्यम से स्वयंसेवक में 'जब कहा गया, उसी समय कार्य करना', 'मिलकर करना', 'साथ-साथ करना' और 'तालमेल बनाकर चलना' जैसे सामूहिक गुणों का विकास होता है। इसी प्रकार संचलन से भी साथ मिलकर चलने की भावना विकसित होती है।

गीत के समय मन की भावनाएं जागृत होती हैं। देशभक्ति, त्याग, बलिदान और समर्पण की भावना का निर्माण होता है। संघ की शाखा से देशभक्त, प्रामाणिक, भेदभाव से मुक्त, निस्वार्थ, समर्पित और समाज के प्रति जागरूक स्वयंसेवक तैयार होता है। सहभोज के माध्यम से स्वयंसेवक सभी के घरों का भोजन मिल-बांटकर खाते हैं। इस प्रक्रिया में छुआछूत, अस्पृश्यता तथा ऊंच-नीच का भाव स्वयंसेवकों के मन में नहीं रहता।

इस प्रकार 'शाखा' केवल दैनिक कार्यक्रमों का स्थान नहीं, बल्कि व्यक्ति निर्माण की ऐसी कार्य पद्धति है, जो स्वयंसेवक में अनुशासन, समरसता, सहयोग, राष्ट्रभाव, सेवा, त्याग और सामाजिक दायित्व की भावना का निरंतर विकास करती आई है। ■

(लेखक, लक्ष्मीबाई कालेज, दिल्ली में सहायक प्राध्यापक हैं।)

विकसित भारत के निर्माण में महिलाओं की भूमिका

■ शालिनी वर्मा

किसी भी सभ्य समाज की सबसे मजबूत नींव उसकी संस्कृति होती है और उस संस्कृति की पहली ईंट प्रायः एक मां के हाथों रखी जाती है। राष्ट्र केवल सीमाओं, सेनाओं और संविधानों से नहीं बनता। राष्ट्र बनता है उन मूल्यों, विचारों और संस्कारों से, जो परिवार और समाज में पीढ़ी-दर-पीढ़ी विकसित होते हैं। इन संस्कारों के निर्माण और संरक्षण में महिलाओं की भूमिका सदियों से महत्वपूर्ण रही है। इसलिए राष्ट्र के विकास में महिलाओं के योगदान को केवल आंकड़ों या भाषणों तक सीमित नहीं किया जा सकता। यह उस सामाजिक चेतना का हिस्सा है, जो देश के भविष्य को आकार देती है।

भारतीय इतिहास पर दृष्टि डालें तो अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं, जहां महिलाओं ने अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। छत्रपति शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व और विचारों के निर्माण में राजमाता जीजाबाई का योगदान इसका एक प्रेरक उदाहरण है। उन्होंने शिवाजी को केवल युद्धकौशल की शिक्षा नहीं दी, बल्कि उनमें स्वाभिमान, न्यायबोध और स्वराज्य की भावना भी विकसित की। विपरीत परिस्थितियों में दिए गए उनके संस्कारों ने शिवाजी के व्यक्तित्व को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भी 'जय भवानी, जय शिवाजी' के उद्घोष में उस परंपरा की स्मृति दिखाई देती है, जिसमें मातृशक्ति और राष्ट्रधर्म का गहरा संबंध रहा है।

मराठा इतिहास की दूसरी महान विभूति अहिल्याबाई होलकर हैं। उन्होंने सत्ता को व्यक्तिगत वैभव का साधन न बनाकर लोककल्याण का माध्यम बनाया। अपने शासनकाल में उन्होंने जनहित, धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण, यात्रियों की सुविधाओं, घाटों, कुओं और धर्मशालाओं के निर्माण जैसे अनेक कार्य कराए। उनका शासन न्याय, संवेदना और लोककल्याण की भावना के लिए स्मरण किया जाता है। अहिल्याबाई ने यह उदाहरण प्रस्तुत किया कि सत्ता का वास्तविक उद्देश्य समाज की सेवा और प्रजा के कल्याण में निहित है।

राष्ट्र के विकास में शिक्षा की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस संदर्भ में स्त्री शिक्षा का प्रश्न विशेष महत्व रखता है। आचार्य शिवपूजन सहाय ने स्त्री शिक्षा के महत्व पर जोर दिया था। शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं है; वह व्यक्ति में विवेक, आत्मविश्वास और सही-गलत के बीच अंतर करने की क्षमता विकसित करती है। एक शिक्षित और जागरूक महिला अपने परिवार के साथ-साथ समाज को भी सकारात्मक दिशा देने में योगदान कर सकती है। इसीलिए स्त्री शिक्षा को परिवार, समाज और राष्ट्र के विकास से जोड़कर देखा जाना चाहिए।

महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' ने भी स्त्री की स्वतंत्रता और उसके सामाजिक महत्व को रेखांकित किया था। उनके विचारों का मूल संदेश यह था कि समाज की प्रगति महिलाओं की स्थिति से अलग नहीं हो सकती। यदि समाज अपनी आधी आबादी को अवसरों, शिक्षा और सम्मान से वंचित रखता है, तो उसकी समग्र प्रगति संभव नहीं है। इसलिए महिला सशक्तीकरण केवल महिलाओं का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय विकास का प्रश्न है।

भारतीय चिंतन परंपरा में नारी को केवल पुरुष के प्रतिपक्ष के रूप में नहीं देखा गया। यहां नारी को शक्ति, ज्ञान और समृद्धि के विभिन्न रूपों से जोड़ा गया है। सरस्वती ज्ञान की, लक्ष्मी समृद्धि की और दुर्गा शक्ति की प्रतीक हैं। यह प्रतीकात्मक परंपरा इस विचार को व्यक्त करती है कि समाज के संतुलित विकास के लिए ज्ञान, समृद्धि और शक्ति-तीनों आवश्यक हैं।

भारतीय परंपरा में स्त्री-पुरुष संबंधों का एक महत्वपूर्ण आधार सहयोग और समन्वय भी रहा है। अर्धनारीश्वर की संकल्पना स्त्री और पुरुष के परस्पर पूरक अस्तित्व को अभिव्यक्त करती है। इसका व्यापक संदेश यह है कि समाज की उन्नति किसी एक वर्ग के वर्चस्व से नहीं, बल्कि परस्पर सम्मान, समान अवसर और सहयोग से होती है। अधिकारों के साथ कर्तव्य और स्वतंत्रता के साथ दायित्वबोध-ये दोनों ही एक स्वस्थ समाज की आवश्यक शर्तें हैं।

आज हम 21वीं सदी में खड़े हैं। तकनीक, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने दुनिया बदल दी है। लेकिन इसके साथ एक नई चुनौती भी आई है। पश्चिमी उपभोक्तावाद ने

पहचान को लाइक्स, ब्रांड और महंगे फोन में खोजना शुरू कर दिया है। ओटीटी और रील्स की दुनिया में रिश्ते अनुभव बन गए हैं और सीमाएं पुरानी सोच लगने लगी हैं।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के आंकड़े बताते हैं कि 13-17 साल की उम्र में बच्चे बहुत जल्दी डिजिटल दुनिया के प्रभाव में आ रहे हैं। जब मस्तिष्क अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुआ और उसे हर पल "डिजिटल डोपामाइन' मिल रहा हो, तो नैतिकता धुंधली पड़ना स्वाभाविक है। किशोरावस्था वह समय है, जब व्यक्तित्व, आदतों और जीवन-मूल्यों का तेजी से विकास होता है। इसलिए बच्चों और किशोरों को डिजिटल माध्यमों के विवेकपूर्ण उपयोग, समय-प्रबंधन, व्यक्तिगत सीमाओं, आत्मसम्मान और वास्तविक जीवन के संबंधों के महत्व के बारे में समझाना आवश्यक है। यह जिम्मेदारी केवल माता-पिता की नहीं, बल्कि परिवार, विद्यालय और पूरे समाज की है। यह केवल सामाजिक संकट नहीं है, यह राष्ट्रीय संकट है। क्योंकि राष्ट्र की शक्ति उसकी संख्या में नहीं, उसकी युवा पीढ़ी की मानसिकता, अनुशासन और मूल्य-संरचना में होती है।

ऐसे समय में परिवार की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। डिजिटल माध्यमों के संतुलित उपयोग के लिए परिवार में संवाद का वातावरण बनाना, बच्चों के साथ नियमित बातचीत करना और उन्हें आत्म-मूल्य, जिम्मेदारी तथा व्यक्तिगत सीमाओं के बारे में समझाना आवश्यक है। बच्चों पर केवल नियंत्रण रखने के बजाय उनके साथ विश्वास और संवाद का संबंध विकसित करना अधिक प्रभावी हो सकता है।

राष्ट्रीय पुर्ननिर्माण किसी एक दिन या किसी एक संस्था का कार्य नहीं है। यह पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलने वाली प्रक्रिया है। परिवार उसकी पहली पाठशाला है और बचपन में मिले संस्कार व्यक्ति के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालते हैं। इसी कारण भारतीय परंपरा में मातृत्व को केवल जैविक भूमिका के रूप में नहीं, बल्कि संस्कार और सामाजिक उत्तरदायित्व से जोड़कर देखा गया है।

जीजाबाई ने शिवाजी के व्यक्तित्व को संस्कार दिए, अहिल्याबाई ने अपने शासन से लोककल्याण का उदाहरण प्रस्तुत किया और भारतीय परंपरा की अनेक माताओं ने अपनी संतानों और समाज को दिशा देने में योगदान दिया। इतिहास के इन उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि महिलाओं की भूमिका केवल परिवार तक सीमित नहीं रही; उन्होंने शिक्षा, प्रशासन, संस्कृति, समाज सुधार और राष्ट्र जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ी है।

आज जब हम 'विकसित भारत' की बात करते हैं, तब महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, आर्थिक स्वावलंबन और समान अवसरों को विकास की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा मानना होगा। एक ऐसा समाज, जहां महिलाएं अपनी प्रतिभा और क्षमता के अनुरूप आगे बढ़ सकें, राष्ट्र की समग्र प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

ईंट-पत्थरों से इमारत बनती है, लेकिन मूल्यों, विचारों और संस्कारों से राष्ट्र का निर्माण होता है। इस राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में महिलाएं केवल सहभागी नहीं, बल्कि अनेक स्तरों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली शक्ति हैं। घर से लेकर शिक्षा, समाज, प्रशासन, विज्ञान, कला, उद्यमिता और सार्वजनिक जीवन तक उनका योगदान भारत के वर्तमान और भविष्य को आकार दे रहा है। ■

(लेखक अमाविप की पूर्व राष्ट्रीय मंत्री हैं।)

सुधी पाठकों !

शिक्षा क्षेत्र की प्रतिनिधि पत्रिका के रूप में 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' अगस्त-2026 अंक आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। यह अंक महत्वूर्ण लेख एवं विभिन्न समसामयिक घटनाक्रमों एवं खबरों को समाहित किए हुए हैं। आशा है, यह अंक आपके आवश्यकताओं के अनुरूप उपादेय साबित होगा। कृपया 'राष्ट्रीय छात्रशक्ति' से संबंधित अपने सुझाव एवं विचार हमें नीचे दिए गए संपादकीय कार्यालय के पते अथवा ई-मेल पर अवश्य भेजें : -

'राष्ट्रीय छात्रशक्ति'
26, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,
नई दिल्ली-110002
फोन : 011-23216298
www.chhatrashakti.in
rashtriyachhatrashakti.abvp@gmail.com
www.facebook.com/Rchhatrashakti
www.twitter.com/Rchhatrashakti
www.instagram.com/ Rchhatrashakti



Youth Innovation Holds the Key to India's Agricultural Future

The 2nd North-West Zonal Convention cum National Conference of AGRIVISION–2026, centred on the theme "Role of Youth in Innovation & Entrepreneurship Development in Agriculture and Allied Sectors", was successfully organised at Maharana Pratap Auditorium, RCA, Udaipur. Organised by Vidyarthi Vikas Nidhi in collaboration with Maharana Pratap University of Agriculture and Technology (MPUAT), Udaipur, the two-day convention brought together students, young professionals, researchers, academicians, entrepreneurs and agricultural stakeholders on a common platform to deliberate on the future of Indian agriculture. The convention witnessed participation from 7 universities, with 328 students, 45 faculty members and 27 entrepreneurs, reflecting strong participation from the academic, research and entrepreneurial community in agriculture and allied sectors.

Rajasthan Governor Haribhau Kisanrao Bagde, who attended the inaugural session as Chief Guest, emphasised the need for conservation of agricultural resources and sustainable use of natural resources in the face of increasing pressure on agricultural land. Highlighting the role of emerging technologies, the Governor said Artificial Intelligence, start-ups, innovation and entrepreneurship could play an important role in increasing agricultural productivity. He also called upon youth to reduce food wastage, strengthen the farm-to-consumer system and draw inspiration from India's traditional agricultural knowledge.

The inaugural session was also addressed by Ashwani Sharma, Zonal Organising Secretary, North-West Zone, ABVP and Dr. Pratap Singh, Vice-Chancellor, MPUAT. Dr. Lokesh Gupta, Program Organising Secretary, introduced the programme, while Tanvi Choudhary, National Co-Convener, Agrivision, presented an overview of the organisation. A souvenir was also released during the inaugural

ceremony.

Focus on innovation and entrepreneurship

The inaugural programme was followed by Technical Sessions, the Yuva Session and the Krishi Sansad Session, which focused on innovation, entrepreneurship, employment and emerging career opportunities in agriculture and allied sectors.

Technical Session-I, chaired by Dr. R. B. Dubey, HVC, SKRAU, Bikaner, featured expert lectures by Dr. S. K. Sharma, Dr. Sanjay Kumar and Dr. Suresh Kumar Jain on natural farming, horticulture-based entrepreneurship and animal husbandry enterprises. The session concluded with an interactive discussion between speakers and students.

The Yuva Session, chaired by Dr. V. S. Jaitawat, HVC, AU, Jodhpur, focused on the potential of agri-start-ups, livestock innovation, value addition and agricultural exports. Dr. Arvind Soni and Mohit Sharma of APEDA shared insights into innovative agri-entrepreneurship and strategies for connecting Indian agricultural produce with global markets.

The Krishi Sansad Session, chaired by Dr. Sarla Lakhawat, Dean, CCAS, MPUAT, provided a platform to discuss challenges in agricultural education and the potential of agriculture and livestock-based entrepreneurship as sustainable career alternatives to conventional government employment.

Manish Fate, National Convenor, Agrivision, emphasised the importance of innovation, entrepreneurship and leadership among young people in the agricultural sector. The jury comprising Dr. K. D. Ameta, Dr. J. Choudhary and Dr. B. G. Chhipa deliberated on emerging opportunities and challenges in the sector. The session concluded with remarks by the Chairperson and a vote of thanks by Manoj Sharma, State Co-Convenor, Agrivision, Chittor Prant.

Vande Mataram session and role models

The second day began with a Special Dialect Session on "Vande Mataram ke 150 Varsh", addressed by Ashwani Sharma, North-West Zone Organising Secretary of ABVP. The session highlighted the historical and cultural significance of Vande Mataram and its continuing relevance in promoting national pride, unity and responsibility among the youth.

The Role Model Session, chaired by Dr. Vimla Dunkwal, HVC, AU, Kota, featured talks by Pasha Patel, known as the Bamboo Man of India; Vishal Sanjay Tayde on Tribal Veda; Dr. Sharvan Yadav on organic farming as a profitable enterprise for rural youth and Ankit Jain on Fasal Amrit.

The session offered students practical perspectives on entrepreneurship, innovation, sustainable agriculture and livelihood opportunities, followed by an interactive speaker–student session.

Women's role in agriculture discussed

The conference continued with Technical Session-II, chaired by Dr. Pratap Singh, Vice-Chancellor, MPUAT, which focused on the changing role of women in agriculture.

Dr. Vimla Dunkwal, HVC, AU, Kota, delivered a lecture highlighting the increasing contribution of women to agricultural development, innovation and entrepreneurship. The session was followed by an interaction between speakers and students, concluding remarks and a vote of thanks by Rishi Raj Singh Chundawat, Joint Organising Convenor.

Awards presented at valedictory session

The two-day conference concluded with the Valedictory Session, during which Dr. Amit Kumar, Joint-Organising Secretary, presented a summary of the zonal convention. Vikram Singh Farshwan, National Incharge, Agrivision and Dr. Paras Tank, President, ABVP Chittor Prant also addressed the gathering. Best Oral and Poster Presentation Awards were presented to recognise outstanding contributions by participants.

Dr. Pratap Singh, Vice-Chancellor, MPUAT, addressed the participants, while Dr. C. P. Nama introduced the Organising Committee. The programme concluded with a vote of thanks by Dr. Anshul Sharma, followed by the National Song and National Anthem.

The successful conclusion of the 2nd North-West Zonal Convention-cum-National Conference of AGRIVISION–2026 underlined the growing importance of youth participation in the transformation of Indian agriculture. With participation from seven universities and a combined presence of 328 students, 45 faculty members and 27 entrepreneurs, the conference provided a platform for knowledge exchange, networking, innovation and entrepreneurship, encouraging young people to emerge as innovators, technology adopters, entrepreneurs and future leaders in agriculture and allied sectors. ■

(Rashtriya Chhatrashakti Team)



Model COP 31 Concludes at IIT Roorkee with Call for Greater Indian Leadership on Climate Action

A two-day Model COP 31 conference, organised by Student for Development (SFD) at the IIT Roorkee campus in Saharanpur, concluded on August 10 with a call for stronger youth participation in global climate discourse and greater representation of India's environmental priorities on international platforms.

Students from 21 states across the country, representing 116 nations, participated in the conference and engaged in discussions on a range of environmental issues. Through various sessions, participants presented their perspectives and proposed solutions to challenges related to climate change, carbon emissions, water conservation and sustainable development.

The conference was inaugurated by Kunwar Brijesh Singh, Minister of State in the Uttar Pradesh government, who attended as the chief guest, along with Rahul Gaur, National Incharge of SFD, as the chief speaker. The inaugural ceremony was marked by the traditional lighting of the lamp in the presence of Dr Ajay Singh, Mayor of Saharanpur; Professor Praveen Kumar, Programme Chairman; Ramakant Chaudhary, National

Co-Convener of SFD and Dr Ghanshyam Vats, President of ABVP Meerut Prant.

The conference sought to provide students with an understanding of international climate negotiations and equip them to present India's perspective effectively on global platforms. Discussions also emphasised the importance of increasing the participation of Indian students in international programmes and forums dealing with environmental concerns.

Speaking at the conference, Rahul Gaur said the ongoing geopolitical tensions and conflicts around the world were also having an impact on the environment. He highlighted the growing challenge of carbon emissions and changing weather patterns. Referring to changes in Pacific Ocean temperatures, Gaur said phenomena such as El Niño and La Niña have significant implications for global monsoon patterns. India, he noted, has witnessed unusual weather conditions, including excessive rainfall and landslides in mountainous regions.

He stressed the need to revive traditional and sustainable practices such as tree plantation, rainwater harvesting and the cultivation of less water-intensive crops, including millets and jowar, to address emerging environmental challenges.

Chief Guest Kunwar Brijesh Singh outlined various initiatives undertaken by the Uttar Pradesh government for environmental protection and climate action. He highlighted the 'Ek Ped Maa Ke Naam' campaign, under which saplings are planted during the monsoon season, and said the state has set a target of increasing its green cover to 15 per cent by 2030.

He also referred to the Upavan and Heritage Forest Scheme, under which plantation activities are being undertaken in urban and rural areas, including along roads and around parks. Traditional and historic trees that are more than 100 years old are also being protected as Heritage Trees, he said.

Singh said both the state and central governments are committed to environmental conservation and expressed the hope that more programmes would be jointly organised with students in the future. Such initiatives, he said, would help keep young people aware of environmental challenges and encourage them to contribute to finding solutions.

Prominent environmentalist and Padma Shri awardee Sethpal Singh described the organisation of Model COP 31 as an important initiative for sensitising young people about environmental issues. He said that with COP 31 scheduled to be held in Türkiye, programmes such as Model COP provide students with an opportunity to understand global climate discussions and develop the ability to represent their views effectively.

He emphasised that young people are not only the future of India but also the future of the world, making awareness and understanding of environmental issues essential for the next generation.

In the concluding session, Jaswant Saini, Minister of State for Parliamentary Affairs and Finance, said India remained committed to a global order based on rules and respect for national sovereignty. He said climate action in the coming decade must move beyond ambitious targets and focus on effective implementation, solidarity and shared prosperity. ■

(Rashtriya Chhatrashakti Team)

आपदा में सेवा का संकल्प
असम में बाढ़ पीड़ितों के साथ अभाविप

असम के शिवसागर, चराइदेव और जोरहाट जिलों में आई प्रलयंकारी बाढ़ ने जनजीवन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। बाढ़ से जहां बड़ी संख्या में परिवार प्रभावित हुए हैं, वहीं जन-धन और पशुधन को भी भारी क्षति पहुंची है। इन तीनों जिलों में एक लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में आए हैं। संकट की इस घड़ी में प्रशासन और सरकार के राहत प्रयासों के साथ समाज के विभिन्न वर्ग भी प्रभावित लोगों की सहायता के लिए आगे आए हैं। इसी क्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने सेवा को अपना दायित्व मानते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में निरंतर राहत एवं सेवा अभियान प्रारंभ किया है।



22 जुलाई 2026 से शिवसागर, चराइदेव और जोरहाट जिलों के विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अभाविप के कार्यकर्ता लगातार सेवा कार्य में जुटे हुए हैं। अभियान को व्यापक स्वरूप देने के लिए परिषद ने प्रांत स्तर पर कार्ययोजना तैयार की, जिसके माध्यम से असम के विभिन्न जिलों के कार्यकर्ताओं को राहत एवं सेवा कार्यों से जोड़ा गया।

इस अभियान के अंतर्गत बाढ़ प्रभावित परिवारों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए असम के विभिन्न जिलों में खाद्य सामग्री, शुद्ध पेयजल, उपयोग योग्य कपड़े, ब्लीचिंग पाउडर तथा दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं का संग्रह किया गया। कार्यकर्ताओं ने इन सामग्रियों को प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाकर जरूरतमंद परिवारों के बीच वितरित किया। राहत सामग्री पहुंचाने के साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में श्रमदान और अन्य आवश्यक सेवा कार्य भी किए जा रहे हैं।

स्थानीय कार्यकर्ताओं की सक्रिय भूमिका के साथ असम के विभिन्न जिलों से कार्यकर्ता भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। अनेक कार्यकर्ता एक-एक दिन के लिए प्रभावित गांवों में जाकर राहत सामग्री के वितरण, श्रमदान और जनसहयोग के कार्यों में सहभागी बन रहे हैं। इस प्रकार सेवा अभियान को केवल राहत सामग्री वितरण तक सीमित न रखते हुए प्रभावित परिवारों के बीच प्रत्यक्ष सहभागिता का स्वरूप दिया गया है।

22 जुलाई से प्रारंभ हुआ यह सेवा अभियान निरंतर जारी है। असम के विभिन्न क्षेत्रों से एकत्र की जा रही राहत सामग्री को आवश्यकतानुसार शिवसागर, चराइदेव और जोरहाट के प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचाया जा रहा है। बाढ़ के बाद उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए शुद्ध पेयजल, स्वच्छता से संबंधित सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुओं को भी राहत अभियान में प्राथमिकता दी जा रही है।

अभाविप के अनुसार, अब तक 90 से अधिक गांवों में 8,000 से ज्यादा बाढ़ प्रभावित लोगों तक सहायता पहुंचाई जा चुकी है। इस सेवा अभियान में पूरे असम से 585 से अधिक कार्यकर्ताओं ने विभिन्न स्तरों पर सहभागिता की है। बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के बीच निरंतर चल रहा यह अभियान समाज के प्रति संवेदनशीलता, सामूहिक उत्तरदायित्व और सेवा-भाव की भावना को सामने रखता है।

आपदा की घड़ी में राहत पहुंचाना केवल तात्कालिक सहायता का कार्य नहीं, बल्कि समाज के साथ खड़े होने का संकल्प भी है। अभाविप का यह अभियान इसी भावना के साथ प्रभावित परिवारों तक पहुंचने और आवश्यकता के समय उनके साथ खड़े रहने का प्रयास है। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

'नेपथ्य में रहकर राष्ट्र पुनर्निर्माण के साधक थे मदनदास जी'

अभाविप के पूर्व राष्ट्रीय संगठन मंत्री स्व. मदनदास देवी के नाम पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान



महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के करमाला स्थित शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) का नामकरण अभाविप के पूर्व राष्ट्रीय संगठन मंत्री मदनदास देवी की स्मृति में 'स्व. मदनदास देवी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान' किया गया। 30 जून को आयोजित नामकरण समारोह में मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर उपस्थित रहे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वीडियो संदेश के माध्यम से शुभकामनाएं प्रेषित कीं, जबकि कौशल विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में विधायक नारायण पाटिल, पूर्व विधायक राम सातपुते, मदनदास जी के भ्राता खुशालदास देवी, व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय के सतीश सूर्यवंशी, संस्थान की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष जितेंद्र राठी, राधेश्याम देवी सहित अनेक गणमान्यजन उपस्थित रहे।

स्व. मदनदास जी देवी के जीवन एवं राष्ट्रकार्य को स्मरण करते हुए मुख्य वक्ता सुनील आंबेकर ने कहा कि मदनदास जी संघ की तपःपूत परंपरा में गढ़े गए सार्वजनिक जीवन के आदर्श कार्यकर्ता थे। संगठन और राष्ट्रकार्य को गति देने के लिए उन्होंने सदैव नेपथ्य में रहकर कार्य किया और अंतिम समय तक अपने जीवनव्रत का निर्वहन किया।

उन्होंने कहा कि देश की वास्तविक प्रगति के लिए युवा शक्ति को उचित दिशा देना आवश्यक है। इसी भाव के साथ मदनदास जी ने देशभर में विद्यार्थियों के एक व्यापक एवं रचनात्मक आंदोलन को खड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैश्विक व्यापार के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए राष्ट्रीय हितों की रक्षा किस प्रकार की

जाए, इसके लिए उन्होंने युवा पीढ़ी में स्वदेशी का विचार स्थापित किया।

शहरीकरण की बढ़ती चुनौती की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए श्री आंबेकर ने कहा कि केवल महानगरों को विकसित करने से राष्ट्र समृद्ध नहीं हो सकता। आर्थिक विकास के अवसरों को गांवों तक पहुंचाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों का सुदृढ़ तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत को विकास की दिशा में आगे बढ़ते हुए केवल तकनीकी प्रगति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि तकनीक के साथ मनुष्य एवं चरित्र निर्माण को भी प्राथमिकता देनी होगी।



उन्होंने कहा कि मदनदास जी ने अपने जीवनकाल में अनेक योग्य जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, चिकित्सकों और समाजसेवियों के निर्माण में भूमिका निभाई। हिंदू समाज को संगठित करते हुए उन्होंने ग्रामीण, जनजातीय एवं सुविधाहीन समाज को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया। पूर्वोत्तर भारत की राष्ट्रीय एकात्मता के लिए गुवाहाटी में युवा विकास केंद्र की स्थापना भी उनके कार्यों की महत्वपूर्ण कड़ी रही।

मदनदास जी की दूरदृष्टि का उल्लेख करते हुए श्री आंबेकर ने कहा कि बदलते समय की आवश्यकताओं के अनुरूप आईटीआई जैसे संस्थानों में भी निरंतर परिवर्तन एवं सुधार आवश्यक हैं। इसी चिंतन के साथ मदनदास जी ने 1989-90 में नागपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के माध्यम से ऐतिहासिक राष्ट्रीय आईटीआई सम्मेलन का आयोजन कराया था।

उन्होंने कहा कि करमाला आईटीआई का मदनदास जी के नाम पर किया गया नामकरण उनके इसी चिंतन और संकल्प की सार्थक परिणति है। यह संस्थान आने वाली पीढ़ियों को कौशल, स्वावलंबन और राष्ट्रनिर्माण के प्रति प्रतिबद्धता की प्रेरणा देगा।

मदनदास जी ने जगाया एकात्मता का भाव : देवेंद्र फडणवीस

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने संदेश में स्व. मदनदास जी देवी की स्मृतियों को नमन करते हुए कहा कि युवाओं में राष्ट्र निर्माण की चेतना और राष्ट्रीय एकात्मता का भाव जागृत करने में उनका योगदान उल्लेखनीय रहा। विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय जीवन की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए उन्होंने जीवनपर्यंत प्रयास किए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान समय में आईटीआई केवल तकनीकी प्रशिक्षण देने वाले संस्थान नहीं हैं, बल्कि देश के लिए कुशल एवं सक्षम मानव संसाधन तैयार करने के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में इन संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

करमाला आईटीआई में खुलेगी टाटा इंस्टीट्यूट की शाखा

महाराष्ट्र के कौशल विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा ने कहा कि मदनदास जी आत्मनिर्भर भारत के निर्माण तथा युवाओं को स्वावलंबी बनाने के प्रबल समर्थक थे। उनके विचारों को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार आईटीआई संस्थानों के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दे रही है।

उन्होंने बताया कि राज्य में आईटीआई संस्थानों के आधुनिकीकरण के लिए 5,700 करोड़ का प्रावधान किया गया है। युवाओं को केवल रोजगार प्राप्त करने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनाने के उद्देश्य से आधुनिक एवं रोजगारपरक पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। आईटीआई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) एवं इलेक्ट्रिकल जैसे पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जा चुके हैं तथा आगामी वर्ष में पांच नए उन्नत पाठ्यक्रम जोड़े जाएंगे। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं का संकट युवाओं के भरोसे की परीक्षा



■ डा. मौसमी पॉल

झारखंड केवल खनिज संपदा और प्राकृतिक संसाधनों की भूमि नहीं, बल्कि संघर्ष, स्वाभिमान और अधिकारों के लिए आवाज उठाने वाली जनता की धरती भी है। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर बने झारखंड के गठन के पीछे एक ऐसी व्यवस्था का सपना था, जिसमें स्थानीय युवाओं को अवसर मिले, प्रशासन जवाबदेह हो और विकास का लाभ राज्य के लोगों तक पहुंचे। लेकिन राज्य गठन के लगभग 26 वर्ष बाद झारखंड का युवा एक नए सवाल से जूझ रहा है-क्या उसकी मेहनत और योग्यता उसके भविष्य का भरोसेमंद आधार बन सकती है?

2026 में जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं को लेकर उभरा युवा असंतोष इसी प्रश्न को सामने लाता है। परीक्षा में विलंब, रद्दीकरण, कथित पेपर लीक, अनियमितताओं और चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर उठते सवालों ने युवाओं के बीच असंतोष पैदा किया है। आंदोलनकारियों की प्रमुख मांगों में संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करना, निष्पक्ष जांच और भर्ती व्यवस्था में व्यापक सुधार शामिल रहे।

जेपीएससी और जेएसएससी लाखों युवाओं के लिए केवल सरकारी संस्थाओं के नाम नहीं हैं। इनके माध्यम से वे अपने सामाजिक और आर्थिक भविष्य को बदलने का प्रयास करते हैं। एक अभ्यर्थी वर्षों तक तैयारी करता है, परिवार की आर्थिक कठिनाइयों के बीच पढ़ता है और अपनी उम्र तथा सीमित अवसरों के बावजूद लगातार प्रयास करता है। ऐसे में परीक्षा का टलना केवल कैलेंडर की तारीख बदलना नहीं है। इसके साथ अभ्यर्थी की उम्र, आर्थिक दबाव और पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। कई बार अधिकतम आयु सीमा भी समाप्त होने लगती है। इसलिए भर्ती प्रक्रिया में अनिश्चितता स्वयं एक गंभीर



समस्या बन जाती है। जेपीएससी की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षाओं और विशेष रूप से 14वीं जेपीएससी परीक्षा को लेकर उठे सवालों ने इसी चिंता को गहरा किया। हालांकि किसी भी अनियमितता के आरोप और उनके जांच में सिद्ध होने के बीच अंतर करना जरूरी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में आरोपों की निष्पक्ष जांच और दोष सिद्ध होने पर कार्रवाई ही उचित रास्ता है।

झारखंड लोक सेवा आयोग-स्नातक स्तरीय परीक्षा (जेएसएससी-सीजीएल) भी 2026 के युवा आंदोलन के केंद्र में रहा। रिपोर्टों के अनुसार लंबे आंदोलन के बाद सरकार ने परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया तथा एक आउटसोर्स एजेंसी द्वारा 2014 से कराई गई विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया की पुनरावलोकन का निर्णय सामने आया।

परीक्षा रद्द करने से एक समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन दूसरी चुनौती भी पैदा होती है। कथित अनियमितताओं के कारण ईमानदार अभ्यर्थी भी प्रभावित होते हैं। इसलिए किसी परीक्षा को रद्द करना अंतिम समाधान नहीं हो सकता। इसके साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जिन अभ्यर्थियों ने नियमों के अनुसार परीक्षा दी, उनके हितों की रक्षा कैसे की जाए।

रोजगार से अधिक विश्वास का प्रश्न

प्रतियोगी परीक्षाएं आर्थिक और सामाजिक रूप से अलग-अलग पृष्ठभूमि के युवाओं को योग्यता के आधार पर आगे बढ़ने का अवसर देती हैं। इसलिए इनकी निष्पक्षता केवल प्रशासनिक विषय नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय का प्रश्न भी है।

यदि किसी विद्यार्थी को यह विश्वास होने लगे कि परिणाम उसकी योग्यता से अधिक किसी अनियमितता, प्रभाव या व्यवस्था की कमजोरी से तय हो सकता है, तो नुकसान केवल एक परीक्षा का नहीं होता। पूरी संस्थागत व्यवस्था की विश्वसनीयता प्रभावित होती है।

यही कारण है कि पेपर लीक या परीक्षा अनियमितता के आरोपों को केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। प्रश्न यह होना चाहिए कि यदि अनियमितता हुई तो वह कैसे हुई, जिम्मेदारी किसकी थी, परीक्षा संचालन में लगी एजेंसी की भूमिका क्या थी और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही कैसे तय होगी। इन

सवालों का उत्तर तथ्यों, दस्तावेजों और निष्पक्ष जांच से ही मिल सकता है।

आंदोलन के पीछे की बेचैनी

2026 का युवा आंदोलन किसी एक घटना का परिणाम नहीं माना जा सकता। इसके पीछे परीक्षा में देरी, भर्ती प्रक्रिया को लेकर विवाद, सीमित रोजगार अवसर और वर्षों से जमा होती निराशा का प्रभाव दिखाई देता है। रांची सहित प्रदेश भर में छात्रों के प्रदर्शन और अगस्त 2026 में विधानसभा की ओर मार्च की खबरों ने इस असंतोष को व्यापक सार्वजनिक विमर्श का विषय बनाया। आंदोलन में राजनीतिक और सामाजिक संगठनों की भूमिका हो सकती है, लेकिन इसके मूल में रोजगार की तैयारी कर रहे युवाओं की चिंता को समझना आवश्यक है। नौकरी की तैयारी करने वाला युवा सबसे पहले एक विद्यार्थी है। उसकी मांग किसी राजनीतिक नारे से पहले अपने भविष्य की सुरक्षा और अपनी मेहनत की विश्वसनीयता की मांग है।

समाधान केवल परीक्षा रद्द करना नहीं

झारखंड की भर्ती व्यवस्था को तत्काल और दीर्घकालिक दोनों स्तरों पर सुधार की आवश्यकता है। सबसे पहले वार्षिक भर्ती कैलेंडर सुनिश्चित होना चाहिए, ताकि अभ्यर्थियों को परीक्षा से नियुक्ति तक की स्पष्ट समय-सीमा पता हो। प्रश्नपत्र की सुरक्षा, डिजिटल डेटा और सर्वर की निगरानी, सीसीटीवी, बायोमेट्रिक सत्यापन तथा परीक्षा केंद्रों की निगरानी को मजबूत करना होगा। आउटसोर्स एजेंसियों की भूमिका और जवाबदेही स्पष्ट करनी होगी। अभ्यर्थियों के लिए स्वतंत्र शिकायत निवारण तंत्र और आंसर-की तथा परिणाम प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता आवश्यक है। यदि किसी परीक्षा को रद्द करना पड़े तो ईमानदार अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा के लिए स्पष्ट नीति होनी चाहिए। इसी प्रकार किसी भी अनियमितता की जांच समयबद्ध तरीके से पूरी कर उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए।

भर्ती व्यवस्था में व्यापक सुधार की आवश्यकता

वर्तमान स्थिति सरकार के लिए केवल संकट नहीं, बल्कि भर्ती व्यवस्था में व्यापक सुधार का अवसर भी है। निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई, ईमानदार अभ्यर्थियों के हितों की रक्षा और पारदर्शी भर्ती प्रणाली विश्वास बहाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। विपक्ष और राजनीतिक संगठनों की भी जिम्मेदारी है कि युवाओं की वास्तविक समस्याओं को केवल राजनीतिक लाभ का माध्यम न बनाया जाए। जहां अनियमितता हो, वहां तथ्य आधारित विरोध हो और जहां आरोप प्रमाणित न हों, वहां तथ्यों को सामने रखा जाए।

भर्ती व्यवस्था किसी एक सरकार या दल की नहीं, बल्कि राज्य की संस्थागत व्यवस्था है।

युवा क्या चाहता है?

झारखंड के युवा की मांग बहुत बुनियादी है-

निष्पक्ष परीक्षा,
समय पर परीक्षा,
समय पर परिणाम,
समय पर नियुक्ति
और अपनी मेहनत पर विश्वास।

वह चाहता है कि उसकी उत्तर पुस्तिका उसकी योग्यता के आधार पर जांची जाए। जिस परीक्षा के लिए उसने वर्षों तैयारी की है, उसमें किसी और की गलती के कारण उसका भविष्य प्रभावित न हो। वह चाहता है कि अनियमितता करने वाले पर कार्रवाई हो और ईमानदार अभ्यर्थी सुरक्षित रहे।

झारखंड के गठन का सपना केवल एक नए राज्य का निर्माण नहीं था। वह बेहतर अवसर, जवाबदेह प्रशासन और सम्मानजनक भविष्य का सपना भी था। आज जेपीएससी और जेएसएससी से जुड़े विवाद उसी सपने की कसौटी हैं। एक परीक्षा का प्रश्नपत्र केवल कागज नहीं होता। उसके साथ किसी विद्यार्थी के वर्षों का परिश्रम, परिवार की उम्मीद और भविष्य की संभावना जुड़ी होती है। इसलिए भर्ती परीक्षा की विश्वसनीयता को केवल प्रशासनिक विषय मानना पर्याप्त नहीं होगा।

2026 का युवा असंतोष एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। युवाओं को केवल रोजगार के आंकड़े नहीं, बल्कि ऐसी रोजगार व्यवस्था चाहिए जिस पर वे विश्वास कर सकें। झारखंड को ऐसी भर्ती व्यवस्था बनानी होगी जिसमें परीक्षा से नियुक्ति तक हर चरण पारदर्शी हो, अनिश्चितता के लिए जगह कम से कम हो, शिकायतों की निष्पक्ष जांच हो और दोषी पाए जाने पर जवाबदेही तय हो। क्योंकि झारखंड की खनिज संपदा उसकी प्राकृतिक पूंजी है, लेकिन उसका युवा उसकी सबसे बड़ी मानवीय पूंजी है। किसी भी राज्य का भविष्य केवल उसकी खदानों से नहीं, बल्कि इस बात से तय होता है कि वह अपने युवाओं की मेहनत, योग्यता और सपनों के साथ कितना न्याय करता है। ■

(लेखक अभाविप झारखंड की प्रांत अध्यक्ष हैं।)



। रांची ।

जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षा अनियमितताओं के विरुद्ध अभाविप का हल्ला बोल, मुख्यमंत्री आवास से विधानसभा तक प्रदर्शन

झारखंड में झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग(जेएसएससी) की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के आरोपों को लेकर विद्यार्थियों ने हल्ला बोल दिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप) ने रांची में मुख्यमंत्री आवास से लेकर विधानसभा तक प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री आवास की ओर निकाले गए छात्र मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारियों के बाद अभाविप ने विधानसभा घेराव का आह्वान किया। दोनों प्रदर्शनों में पुलिस बल के इस्तेमाल, लाठीचार्ज, वॉटर कैनन और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर अभाविप ने सरकार पर सवाल उठाए। अभाविप ने संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, पूरे प्रकरण की केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जांच कराने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।

अभाविप के अनुसार, 8 अगस्त को डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय से मुख्यमंत्री आवास की ओर छात्र मार्च निकाला गया, मार्च के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया एवं अभाविप झारखंड प्रांत मंत्री प्रकाश टूटी, महानगर मंत्री तुषार दुबे सहित कई विद्यार्थियों और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। अभाविप का कहना है कि जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की शिकायतों के बाद परिषद ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने के साथ विभिन्न शिक्षण संस्थानों और शहरों में हस्ताक्षर अभियान चलाया। इसके बाद राज्य के जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किए गए। अभाविप के अनुसार, 30-31 जुलाई से विद्यार्थियों की मांगों को लेकर आंदोलन चलाया जा रहा था। मुख्यमंत्री आवास तक छात्र मार्च इसी क्रम

का हिस्सा था।

अभाविप ने परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता, विद्यार्थियों की शिकायतों की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठाई। अभाविप का कहना है कि विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे पर सरकार को संवाद के माध्यम से समाधान निकालना चाहिए।

लाठीचार्ज के विरोध में विधानसभा घेराव

मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में अभाविप ने 11 अगस्त को विधानसभा घेराव का आह्वान किया। प्रदेश के विभिन्न जिलों से विद्यार्थी और कार्यकर्ता रांची पहुंचे। अभाविप ने आरोप लगाया कि कई स्थानों पर विद्यार्थियों और कार्यकर्ताओं को रांची पहुंचने से रोकने का प्रयास किया गया। पुराने विधानसभा परिसर के निकट प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तनाव की स्थिति बनी। अभाविप का कहना है कि प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हुए। अभाविप ने कहा कि राष्ट्रीय महामंत्री डा. वीरेंद्र सिंह सोलंकी, राष्ट्रीय मंत्री अभय प्रताप सिंह और प्रदेश मंत्री प्रकाश टूटी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया।

एसआईटी की जांच पर प्रश्नचिह्न, सीबीआई जांच की मांग

परीक्षा अनियमितताओं की जांच को लेकर अभाविप ने राज्य सरकार की ओर से गठित विशेष जांच टीम(एसआईटी) की कार्यप्रणाली पर भी प्रश्न उठाए हैं। अभाविप का कहना है कि जांच समिति में बदलावों के कारण विद्यार्थियों के बीच जांच की निष्पक्षता को लेकर संदेह पैदा हुआ है। अभाविप ने जेपीएससी और जेएसएससी से जुड़ी जिन परीक्षाओं की निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्न उठे हैं, उनकी सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। अभाविप ने विशेष रूप से जेएसएससी(सीजीएल) परीक्षा को रद्द कर दोबारा निष्पक्ष प्रक्रिया से आयोजित कराने की मांग उठाई है। साथ ही कथित पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई है।

परीक्षा व्यवस्था में संस्थागत सुधार की मांग

अभाविप का कहना है कि केवल दोषियों पर कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं होगा। प्रश्नपत्र की सुरक्षा, परीक्षा केंद्रों की निगरानी, परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर स्थायी सुधार किए जाने चाहिए। अभाविप ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की अनियमितता विद्यार्थियों के वर्षों के परिश्रम और उनके भविष्य को प्रभावित करती है। इसलिए परीक्षा और भर्ती संस्थाओं की जवाबदेही तय करने के साथ ऐसी व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए, जिसमें पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और भरोसेमंद हो।

लाठीचार्ज से नहीं दबेगी विद्यार्थियों की आवाज

अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री डा. वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में सामने आई अनियमितताओं का मुद्दा केवल झारखंड के विद्यार्थियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता और पारदर्शिता से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना सरकार और संबंधित परीक्षा संस्थाओं की जिम्मेदारी है।

डा.सोलंकी ने विद्यार्थियों के आंदोलन के दौरान पुलिसिया कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए जेपीएससी-जेएसएससीपरीक्षा अनियमितताओं की सीबीआई जांच और जेएसएससी(सीजीएल) परीक्षा रद्द करने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि अभाविप विद्यार्थियों की मांगों को लेकर प्रदेशभर में अभियान और आंदोलन जारी रखेगी।

अभाविप झारखंड के प्रदेश मंत्री प्रकाश टूटी ने कहा कि कथित पेपर लीक और परीक्षा अनियमितताओं के कारण हजारों विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर चिंता पैदा हुई है। उन्होंने सरकार से विद्यार्थियों की मांगों पर संवाद के माध्यम से समाधान निकालने की मांग की।

उन्होंने कहा कि जिन परीक्षाओं की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठे हैं, उनकी निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए और दोषियों पर कार्रवाई के साथ परीक्षा व्यवस्था में आवश्यक संस्थागत बदलाव किए जाने चाहिए। अभाविप ने संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, सीबीआई जांच कराने, दोषियों पर कार्रवाई करने और परीक्षा-भर्ती व्यवस्था में स्थायी सुधार की मांग दोहराई है। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

Karnataka State Auctioning the Throne of Education The Curse of Bribery on the Sacred Field of Education!

■ Mouliteja Aspari

Karnataka is a sacred land, enriched by the patronage of learning during the Vijayanagara Empire and blessed as the birthplace of untarnished luminaries such as Sir M. Visvesvaraya. Yet, it is deeply concerning that on this very soil today, the education system and the arena of government recruitment are increasingly being accused of turning into an open marketplace.

While lakhs of unemployed young men and women toil day and night to secure their future through education and competitive examinations, allegations of corruption in recruitment to the Karnataka Public Service Commission (KPSC) have raised serious questions about the integrity of the system. Allegations such as demands for ₹80 lakh for a veterinary doctor post, examinations allegedly being conducted secretly at resorts and the alleged trading of question papers have shaken the confidence of students and job aspirants.

The issue is not merely about a recruitment examination. It strikes at the very foundation of merit, fairness and public trust.

The Emperors of Bribery and Signatures for Sale

History repeatedly demonstrates how corruption and the auctioning of public positions can weaken institutions from within. Karnataka today faces serious allegations that raise precisely such concerns.

The 80 Lakh Auction Process:

Audio clips allegedly revealing a demand of ₹80 lakh for a single veterinary doctor post have created widespread concern among unemployed youth. If recruitment to public posts can allegedly be influenced by money, what happens to the thousands of deserving candidates who spend years preparing for these examinations?

The Destruction of Morality:

A deeper question also emerges: if an individual obtains a public post after allegedly paying ₹80 lakh, what happens to the principle of public service? Will such an individual be able to serve society purely on the basis of merit and responsibility, or will there be a temptation to recover the money allegedly invested through further corruption?

When education and employment are converted into business transactions, the damage goes far beyond a single examination. It threatens the moral foundation upon which future generations build their aspirations.

Rallies in Delhi, Silence in the Home State?

The contrast in political priorities also deserves scrutiny. Why is the urgency shown by state leader D.K. Shivakumar in taking to the streets of Delhi to protest against alleged irregularities concerning NEET not reflected with the same intensity when students and unemployed youth in Karnataka raise serious concerns about recruitment?

Why do political leaders who raise their voices against irregularities elsewhere remain silent when allegations concerning recruitment emerge within their own state?

If the government genuinely wants to establish transparency and accountability, why should there be hesitation in ordering an independent Central Bureau of Investigation (CBI) probe into the allegations surrounding the KPSC and veterinary doctor recruitment?

For thousands of young aspirants, this is not merely a political issue. It is about years of hard work, family sacrifices and their hopes for a dignified future.

Minister Priyank Kharge's Negligent Attitude-A Black Mark on Democracy!

The conduct of Minister Priyank Kharge has also come under sharp criticism in this context. Questions had previously been raised regarding alleged irregularities in the recruitment of Assistant Executive Engineers (AEE) under the Rural Development

Department. Critics have questioned the government's response to those concerns.

Now, allegations have also emerged regarding the alleged protection or indirect shielding of an IAS officer serving as KPSC Controller of Examinations during an Enforcement Directorate (ED) raid. These allegations require transparent investigation and a clear public response from the government.

The anger of unemployed youth has further intensified over remarks attributed to the minister regarding their protest and hunger strike. The statement - *'First go on a 22-day hunger strike, then we will lathi-charge you, and after that, we will think about resigning'*- has been cited by protesters as an example of the government's alleged insensitive attitude towards unemployed youth.

For youth people who have invested years preparing for government examinations, such remarks can deepen the perception that their concerns are not being taken seriously.



The Roar of Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad

The Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) has declared that it will not remain silent over what it describes as injustice against students and unemployed youth in Karnataka. To raise its voice on issues concerning student rights, recruitment transparency and the integrity of the education system, ABVP has given the call for "Bengaluru Chalo."

According to the ABVP, instead of addressing the concerns of protesting students and unemployed youth, the government responded with police action, including a lathi-charge. ABVP senior karyakarta were also arrested during the agitation. The ABVP has strongly condemned the action, alleging that the government is attempting to suppress the voices of those demanding justice.

The issue therefore goes beyond one organisation or one protest. At its core lies a larger question: Can a system that promises employment on the basis of merit retain the trust of students if allegations of money and influence continue to surround recruitment?

The allegations surrounding recruitment have placed the Karnataka government under serious pressure to demonstrate transparency and accountability.

The unemployed youth of Karnataka are not asking for favours. They are demanding that the system in which they have placed their faith should remain fair, transparent and based on merit.

The ABVP has issued a strong ultimatum to the government: the allegations surrounding the KPSC recruitment process should be handed over to the CBI for an independent investigation, and accountability should be fixed upon those found responsible.

History is impartial. Across civilisations, the weakening of institutions through corruption has often carried consequences far greater than the original wrongdoing. When seats of learning, systems of justice and public offices are perceived to be available for sale, public faith begins to collapse.

Karnataka's unemployed youth have invested their time, energy and dreams in the hope of a fair opportunity. Their aspirations cannot be allowed to become casualties of corruption.

The government must now answer the questions being raised by students and job aspirants. The demand is clear: protect merit, ensure transparency, investigate the allegations independently and fix responsibility wherever wrongdoing is established.

If the government continues to ignore the grievances of unemployed youth, the political consequences of that anger will ultimately be determined by the very citizens whose aspirations are at stake. ■



ABVP Protests in Bengaluru, Demands CBI Probe into Alleged KPSC Recruitment Scam

The Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad (ABVP) staged protests at several locations in Bengaluru, including Freedom Park, Maurya Circle and near the Chief Minister's office, demanding an independent investigation into alleged irregularities in Karnataka Public Service Commission (KPSC) recruitment and seeking a probe by the Central Bureau of Investigation (CBI).

The agitation was centred on allegations surrounding the recruitment of 400 Veterinary Officers. Candidates and complainants have alleged manipulation of the recruitment process, including question-paper leaks, tampering with Optical Mark Recognition (OMR) sheets and payments running into several lakhs of rupees for securing government jobs. The allegations are being investigated by the authorities and remain subject to the outcome of the ongoing proceedings.

During the protests, thoushands of ABVP karyakarta gathered at different locations after police restricted access to Freedom Park. Some protesters moved towards Maurya Circle and Kumar Krupa Road, near the Chief Minister's official office. Police deployed additional personnel and detained several protesters after attempts to proceed towards restricted areas.

ABVP said the alleged irregularities had affected the confidence of thousands of candidates who spend years preparing for competitive examinations.

Addressing protesters, ABVP Karnataka state secretary Yashwant said the ABVP would continue its agitation until the government agreed to an independent investigation.

'Government recruitment must be based on merit and transparency. Allegations that money was demanded from candidates for government posts strike at the aspirations of thousands of young people preparing for competitive examinations,' he said.

ABVP Karnataka state joint secretary Dhanush alleged that complaints regarding irregularities

in KPSC recruitment were not limited to a single examination. He called for an investigation covering the wider recruitment process and demanded action against officials and other persons found responsible.

The ABVP has also demanded greater transparency in the examination process, stronger digital safeguards, independent monitoring of examination and evaluation procedures and publication of a fixed annual examination calendar.

The controversy intensified following the registration of cases in connection with the recruitment of Veterinary Officers. A Karnataka High Court order records that an FIR registered in July 2026 alleged manipulation of OMR sheets and favouring of certain candidates in the recruitment examination. The court proceedings also record that the investigation was continuing and that examination-related documents had been seized.

The suspended KPSC chairman, Shivashankarappa S. Sahukar, has also been questioned in connection with the investigation. The Karnataka Police CID issued him a notice to appear before investigators in August in connection with the alleged Veterinary Officer recruitment fraud.

ABVP said merely taking action against individual officials would not be sufficient and called for institutional reforms in KPSC to ensure that future recruitment examinations are conducted transparently.

The organisation has proposed measures including a fixed annual examination calendar on the lines of the Union Public Service Commission, greater use of technology to secure examination and evaluation systems, independent audits and stronger safeguards against manipulation.

ABVP karyakarta said they would submit a memorandum to Governor Thaawarchand Gehlot seeking an independent probe and reiterated that the agitation would continue until their demands for accountability, transparency and recruitment based on merit are addressed. ■

(Rashtriya Chhatrashakti Team)

ABVP's Key Demands

Probe the role of all KPSC members, including the Commission Chairman, in the matter.

Order a high-level investigation into the matter either by the CBI or through a judicial inquiry.

Set up a fast-track court for expeditious hearing and disposal of the cases.

Strengthen transparency in competitive examinations through effective use of modern technology and necessary reforms in the examination system.

Conduct an impartial probe into all examinations conducted by KPSC over the past five years.



पेपर लीक पर कड़ी कार्रवाई करने से क्यों डर रही पंजाब सरकार : अभाविप

दस सूत्रीय छात्र मांगों को लेकर अभाविप ने किया पंजाब विधानसभा का घेराव



शिक्षा क्षेत्र में लंबे समय से व्याप्त समस्याओं के समाधान और विद्यार्थियों से जुड़े विभिन्न मुद्दों को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (अभाविप), पंजाब ने आंदोलन तेज करते हुए 5 अगस्त को दस सूत्रीय मांगों को लेकर पंजाब विधानसभा का घेराव किया। प्रदर्शन में पंजाब के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं एवं अभाविप कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। अभाविप ने पेपर लीक की घटनाओं पर रोक, छात्रसंघ चुनावों की बहाली, शिक्षा व्यवस्था में सुधार, स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति, निष्पक्ष एवं पारदर्शी परीक्षा प्रणाली सहित विद्यार्थियों से जुड़े अन्य मुद्दों के समाधान की मांग की।

अभाविप का कहना है कि पंजाब में लगातार सामने आ रही पेपर लीक की घटनाएं, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताएं, शिक्षकों के रिक्त पद और छात्रसंघ चुनावों पर रोक जैसी समस्याओं के कारण विद्यार्थियों का शिक्षा व्यवस्था पर विश्वास प्रभावित हुआ है। संगठन ने कहा कि इन विषयों को लेकर वह लंबे समय से आवाज उठा रहा है और सरकार को विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए।

अभाविप के राष्ट्रीय महामंत्री डा वीरेंद्र सोलंकी ने कहा कि पंजाब गुरुओं की धरती है, लेकिन आज यहां के युवा उच्च शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों और विदेशों का रुख कर रहे हैं। उन्होंने इसके लिए राज्य की शिक्षा व्यवस्था और शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े मुद्दों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि अभाविप ने दस सूत्रीय छात्र मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव किया है।

हाल ही में सामने आए फार्मेसी परीक्षा के पेपर लीक मामले का उल्लेख करते हुए अभाविप राष्ट्रीय महामंत्री डा. वीरेंद्र सोलंकी ने कहा कि पेपर लीक आम विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के साथ अन्याय है। उन्होंने मांग की कि प्रदेश में अब तक सामने आए छह पेपर लीक मामलों की गंभीरता से जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी एवं सख्त कानून बनाया जाए। उन्होंने पंजाब सरकार से राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू करने की भी मांग की, ताकि राज्य की शिक्षा व्यवस्था को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित किया जा सके और विद्यार्थियों को पंजाब में ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर मिल सकें।

अभाविप के राष्ट्रीय मंत्री आदित्य ताकियार ने पंजाब सरकार पर शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायीकरण को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य में उच्च शिक्षा नियामक आयोग का गठन किया जाना चाहिए, ताकि अनियमित फीस वृद्धि पर प्रभावी रोक लगाई जा सके और विद्यार्थियों के हितों की रक्षा हो।

अभाविप पंजाब के प्रदेश मंत्री जसकरण सिंह भुल्लर ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य को शिक्षा का मॉडल बनाने के दावे करती है, लेकिन विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर आवाज उठाने वाले संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान अभाविप कार्यकर्ताओं के साथ लाठीचार्ज, धक्का-मुक्की और गिरफ्तारी की गई। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है और सरकार को विद्यार्थियों की आवाज सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए।

जसकरण सिंह भुल्लर ने कहा कि पंजाब के विभिन्न महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के अनेक पद रिक्त हैं, जिसके कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने छात्रसंघ चुनावों की बहाली की मांग करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने का अवसर मिलना चाहिए।



पंजाब विश्वविद्यालय छात्रसंघ के अध्यक्ष गौरववीर सिंह सोहल ने कहा कि सरकार को विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि पंजाब के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों को आवश्यक वित्तीय सहयोग नहीं मिलने के कारण उनका बुनियादी ढांचा प्रभावित हुआ है। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय के लिए लंबित वित्तीय सहयोग का मुद्दा उठाते हुए कहा कि समय पर पर्याप्त फंड उपलब्ध होने से विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल, प्रयोगशालाओं, खेल सुविधाओं और शोध से जुड़े आधारभूत ढांचे को मजबूत किया जा सकता था।

गौरववीर सिंह सोहल ने शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों को नशे से दूर रखने के लिए नशा विरोधी टास्क फोर्स गठित करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि अभाविप का आंदोलन विद्यार्थियों के हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर है। उन्होंने कहा कि जब तक विद्यार्थियों की मांगों पर समाधान नहीं होता और संबंधित मामलों में सरकार जवाबदेही तय नहीं करती, तब तक अभाविप अपना आंदोलन जारी रखेगी। उन्होंने शिक्षा मंत्री हरबंस बैंस के इस्तीफे की भी मांग की। ■

(राष्ट्रीय छात्रशक्ति टीम)

पेपर लीक के विरुद्ध अभाविप द्वारा पंजाब विधानसभा का घेराव





RNI NO.: DELBIL/2017/73636
DATE OF POSTING: 10-11 AUGUST, 2026
DATE OF PUBLISHING: 8 AUGUST, 2026

POST OFFICE: NDGPO, NEW DELHI
POSTING REGISTRATION NO. DL(C)-11/1409/2024-26

केंद्रीय कार्यसमिति बैठक की झलकियां



